कोटद्वार, शनिवार
5 अक्टूबर 2024
वर्षः 46
अंकः 157 पृष्ठः 4
मूल्यः 2.00
RNI No.UTTHIN/2005/16338

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नरेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोन: 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

60 हजार करोड़ के चिट फंड घोटाले में बड़ी कार्रवाई

• देहरादून में बिल्डर पर ईडी की रेड

देहरादून। पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लि. (पीएसीएल) से जुड़े करीब 60 हजार करोड़ रुपये के चिट फंड (पौंजी स्कीम) घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) देहरादून शाखा की टीम ने दून में एक बिल्डर के ठिकानों पर छापेमारी की। टीम ने बड़ी संख्या में जमीन, अन्य संपत्तियों के दस्तावेज और और इलेक्ट्रानिक डिवाइस कब्जे में लिए। ईडी की अलग–अलग टीमें पंजाब और हरियाणा आदि राज्यों में भी घोटाले से जुड़े तमाम व्यक्तियों के घरों और प्रतिष्ठानों की जांच में भी जुटी हैं। शुक्रवार सुबह ईडी की टीम देहरादून में बिल्डर मिकी अफजल के कैनाल रोड स्थित भवन/प्रतिष्ठान के अलावा इसी क्षेत्र में एक वेडिंग प्वाइंट/फार्म पर पहुंची। ईडी की कार्रवाई देर रात तक जारी रहने की उम्मीद है, जिस कारण अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है कि ईडी ने छापेमारी में कितनी नकदी, आभूषण और अभिलेख कब्जे में लिए हैं।

संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई भी शुरू कर सकती ईडी

ईडी जल्द प्रिवेंशन ऑफ मनी लान्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत बिल्डर की संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई भी शुरू कर सकती है। पूर्व में उत्तराखंड में सीबीआई भी पर्ल ग्रुप पर शिकंजा कस चुकी है। तब सीबीआई की ओर से राजस्व परिषद को भेजे गए पत्र के बाद उत्तराखंड में पर्ल ग्रुप से जुड़ी संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, इसके बाद भी भूमाफिया ने जमीनों को खुर्दबुर्द करने का काम किया। जमीनों को खुर्दबुर्द होने से रोकने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों पर थी, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं किए जा सके। यही हाल गोल्डन फारेस्ट की संपत्तियों के मामले में भी सामने आया। दोनों ही कंपनियों के घोटाले एक जैसी प्रकृति के हैं। पांच करोड़ निवेशकों से फर्जी ढंग से जुटाए 60 हजार करोड़ पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लि. (पीएसीएल) के 60 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का संबंध पंजाब निवासी निर्मल सिंह भंगू से है। उसकी अब मौत हो चुकी है।

गैर हाजिर चल रहे शिक्षक, 10 तक कार्मिकों की सूची तलब

काशीपुर। शिक्षा महानिदेशक ने लंबे समय से गैर हाजिर शिक्षकों, कार्मिकों की सूची तलब की है। शिक्षा महानिदेशक ने प्रदेश और जिले के अफसरों को पत्र भेजकर दस अक्तूबर तक रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा अधिकारियों ने अपने अधीनस्थों को अनुपस्थित शिक्षकों की सूची बनाने के समय सीमा के भीतर देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में विधालयी शिक्षा विभाग के कई शिक्षक, कार्मिक लंबी अवधि से गैर हाजिर चल रहे हैं। इसके चलते संबंधित विधालय, कार्यालय में अन्य शिक्षक, कार्मिक की पदस्थापना संभव नहीं हो पा रही है। साथ ही शिक्षण और कार्यालय का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने माध्यमिक, प्रारंभिक,अकादमिक शोध के निदेशकों समेत जिले के शिक्षा अफसरों को निर्देश दिए कि लंबे समय से गैर हाजिर शिक्षक, कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। शिक्षा महानिदेशक ने अफसरों से दस अक्तूबर तक गैर हाजिर शिक्षक, कार्मिकों की सूची अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने को कहा है।

नौगांव में बरातियों को लेकर लौट रही मैक्स खाई में गिरी

दो की मौत, नौ घायल

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार। उत्तराखंड के कोटद्वार में शुक्रवार शाम को दर्दनाक हादसा हो गया। कोटद्वार में जयहरीखाल विकासखंड के नौगांव में बरातियों से भरी मैक्स खाई में गिर गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, नौ लोग घायल हैं।

जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार शाम करीब छह बजे की है। मैक्स बसड़ा गांव से बरातियों को लेकर गुनियाल गांव लौट रही थी। इस दौरान मैक्स अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। घायलों को खाई से निकालने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ पहुंची। लोगों ने बताया कि मैक्स चालक शॉर्टकट संपर्क मार्ग से लौट रहा था, जबकि अन्य

बराती अन्य वाहनों से घर पहुंच चुके हैं। गांव में कोहराम मचा है। वहीं, घायलों को बेस अस्पताल कोटद्वार में भर्ती कराया गया है।

एक नजर

टेस्टिंग के चलते गुल रही बिजली

देहरादून। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के विद्युत वितरण खंड उत्तर डिवीजन के तहत सहस्त्रधारा रोड बिजलीघर से जुड़े क्षेत्रों में शुक्रवार को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे के बीच शटडाउन रहा। पूर्व घोषित शेड्यूल के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में उत्तर डिवीजन के तहत मसूरी के विभिन्न इलाको में भी शटडाउन रहेगा। शुक्रवार को सहस्त्रधारा रोड बिजलीघर के केवल विहार, केवल कला, मधुर विहार, प्रगति विहार, सुमनपुरी, ऋषिनगर, कानन कुंज, नालापानी चौक, रक्षा विहार, आदर्श विहार, विकासलोक, आजादनगर आदि क्षेत्रों में शटडाउन का असर रहा। एसई शहरी क्षेत्र राहुल जैन के मुताबिक बिजलीघरों में टेस्टिंग कार्य के चलते यह शटडाउन लिया जा रहा है। आने वाले दिनों में 14 अक्तूबर को मसूरी के कुंज भवन बिजलीघर से जुड़े क्षेत्र मॉल रोड, लाइब्रेरी चौक, स्प्रिंग रोड, हुसैनगंज, 15 को हैप्पी वैली बिजलीघर से जुड़े क्षेत्र लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, हैप्पी वैली, कंपनी गार्डन, कैम्पटी रोड, 16 को लंढौर बिजलीघर से जुड़े क्षेत्र लंढौर बाजार, कुलड़ी बाजार, मॉल रोड, बुरांशखंडा, एआईआर, 18 अक्तूबर को क्यारकुली बिजलीघर से जुड़े इलाके त्रिक्रेग, बालीगंज, झड़ीपानी, भट्टागांव में बिजली का शटडाउन रहेगा। लिहाजा सम्बंधित इलाकों में बिजली आपूर्ति आंशिक व पूरी तरह से बाधित रह सकती है।

ढाबे पर भोजन के बाद दो लोगों की संदिग्ध हालात में मौत

रुद्रपुर। किच्छा हाईवे स्थित ग्राम कठंगरी के एक ढाबे पर गुरुवार रात भोजन करने के बाद दो लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। एक अन्य युवक का हल्द्वानी के एसटीएच में इलाज किया गया, जहां से उसे छुट्टी दे दी गई है। परिजन नशीले पदार्थ के सेवन से हालत बिगड़ने की बात कह रहे हैं। दोनों शवों के पोस्टमार्टम के बाद बिसरा सुरक्षित रख लिया गया है। गुरुवार शाम पुलिस को सूचना मिली कि किच्छा हाईवे पर सिसैया के पास ग्राम कठंगरी में ट्रक के केबिन में एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त 39 वर्षीय दिनेश पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम कल्याणपुर शहजादनगर, रामपुर यूपी के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं गुरुवार मध्य रात्रि पसहैनी गांव नानकमत्ता निवासी 40 वर्षीय सोनू सिंह पुत्र कुलवंत सिंह और ग्राम सरकड़ा सितारगंज निवासी 39 वर्षीय दीपक बाबा पुत्र केवल कृष्ण को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्साधिकारी डॉ. रविंद्र सिंह ने बताया कि दोनों बीमार लोगों ने जानकारी दी थी कि डोडा यानि नशीले पदार्थ का सेवन किया था। उसके बाद तबीयत बिगड़ गई। गम्भीर हालत के कारण दोनों को रेफर कर दिया था। हल्द्वानी ले जाते वक्त सोनू सिंह ने रास्ते में दम तोड़ दिया। जबकि दीपक को हल्द्वानी के एसटीएच में भर्ती कराया गया, जहां से उसे शुक्रवार को छुट्टी दे दी गई। सितारगंज कोतवाली के एसआई कैलाश देव ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिए हैं।

पाकिस्तान का दौरा करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (रउड) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने शुक्रवार को एक संबोधन के दौरान इसकी पुष्टि की है। इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। यह बैठक 15–16 अक्टूबर को होगी।

अपने संबोधन में रणधीर जयसवाल ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी और अन्य सभी सदस्य देशों को निमंत्रण देना एक प्रोटोकॉल है जिसका पालन कोई भी मेजबान देश करता है। पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया है। मैं इसे एक राजनीतिक स्टंट के रूप में नहीं देखता हूं। हालांकि, मैं प्रधानमंत्री मोदी को इसमें शामिल होते नहीं देखता हूं। उन्होंने आगे कहा, पिछले साल, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने एससीओ विदेश मंत्री की बैठक के लिए भारत का दौरा किया था।

किसान मेला किसानों को समृद्ध बनाने में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका : धामी

• सीएम ने किया अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रगतिशील कृषकों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पं. गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में 116वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और हरेला उद्यान का वर्चुअल शुभारम्भ भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों से आये प्रगतिशील कृषकों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस प्रकार के किसान मेले प्रदेश के किसान भाईयों की उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कृषि मेलों के माध्यम से वैज्ञानिक, किसान एवं उद्यमी एक ही स्थान पर कृषि सम्बन्धी नवीनतम तकनीकों तथा विभिन्न जानकारियों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। किसानों को उन्नत बीज, पौध, कृषि यंत्र और जैविक खाद सहित कृषि से जुड़ी सभी आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस मेले में उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी जानकारियों से हमारे किसान अवश्य लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह मेला वास्तव में कृषि का एक ऐसा कुंभ है, जो किसानों को आधुनिक तकनीकी का बोध कराकर उन्हें समृद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के प्रति पीएम नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो सबसे पहले उन्होंने किसान भाईयों को किसान सम्मान निधि आवंटित करने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए। किसान सम्मान निधि की योजना के जरिए आज उत्तराखंड के भी लगभग 8 लाख से अधिक किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान विशेष रूप से पॉलीहाउस निर्माण के लिए किया है, जिससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत से ह्लउत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्टह्व भी स्वीकृत किया गया है। फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी सरकार विभिन्न स्तर पर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत सेब और कीवी का उत्पादन व्यापक स्तर पर बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में एप्पल और कीवी मिशन की शुरुआत की गई है। एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने वाले किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। कीवी के बगीचे स्थापित करने में भी सरकार हर संभव मदद कर रही है।

डीजीपी अभिनव कुमार के आदेश पर आइटीआइ गैंग पर गैंगस्टर की कार्रवाई, 11 लोग भेजे गए जेल

हल्द्वानी। 26 सितंबर को हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे डीजीपी अभिनव कुमार ने शहर के लिए नासूर बन चुकी आइटीआइ गैंग को उसकी असल जगह पहुंचाने की बात कही थी। अब एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर काठगोदाम पुलिस ने इस गैंग से जुड़े 11 लोगों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक गैंग लीडर भी शामिल है। पेशी के बाद न्यायालय के आदेश पर इन्हें जेल भेज दिया गया है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने गैंग से जुड़े और कई लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है। इन पर भी कार्रवाई होगी।आइटीआइ गैंग के सदस्यों ने हल्द्वानी में आतंक मचा रखा है। सड़क से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में इनका झुंड मारपीट पर उतारू हो जाता है। मई 2022 में शीशमहल में हुए बवाल के बाद उठी अफवाहों से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति तक पैदा हो गई थी। लेकिन पुलिस जांच में पता चला था कि इसमें भी आइटीआइ गैंग का हाथ है।

दूसरी तरफ हाल में पुलिस ने 11 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की थी।

दीपावली पर यूपीसीएल का उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली का तोहफा

देहरादून। दीपावली पर ऊर्जा निगम की ओर से बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली का तोहफा दिया गया है। अक्तूबर महीने में उपभोक्ता जो बिजली खर्च करेंगे, उसमें 70 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से रिफंड उनके बिलों में एडजस्ट होगा। इस तरह अक्तूबर महीने के लिए बिजली 70 पैसे प्रति यूनिट तक सस्ती होगी। फ्यूल एंड पॉवर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट के तहत ऊर्जा निगम हर महीने नई दरें तय करता है। यूपीसीएल के लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2024–25 की औसत विद्युत खरीद लागत 5.03 रुपए प्रति यूनिट मंजूर की है। इससे ऊपर लागत आने पर उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का भार पड़ता है। लागत कम आने पर उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलती है। अप्रैल 2024 से अगस्त 2024 के बीच औसत बिजली खरीद लागत 4.75 रुपए प्रति यूनिट रही। जो आयोग के स्तर पर मंजूर लागत से 28 पैसे प्रति यूनिट कम रही। इस छह प्रतिशत की कमी के कारण बिजली खरीद लागत में 225 करोड़ की बचत हुई। इस बचत को उपभोक्ताओं को लौटाते हुए बिलों में एडजस्ट किया जाएगा।

मुख्य अभियंता कमर्शियल डीएस खाती की ओर से आदेश जारी किया गया।

घरेलू उपभोक्ताओं को 56 पैसे प्रति यूनिट तक की छूट

बिजली बिलों में फ्यूल एंड पॉवर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट में छूट मिलने से घरेलू उपभोक्ताओं को 56 पैसे प्रति यूनिट तक की छूट मिलेगी। बीपीएल उपभोक्ताओं को 21 पैसे, कमर्शियल 81 पैसे, सरकारी ऑफिस 76 पैसे, निजी ट्यूबवेल 24 पैसे, कृषि गतिविधियों 34 पैसे की छूट मिलेगी। एलटी, एचटी उद्योग में 75 पैसे, मिक्सड लोड पर 70 पैसे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के बिलों में 67 पैसे प्रति यूनिट की राहत मिलेगी।

युवती से दुष्कर्म का आरोपी न्यायालय में पेश

देहरादून। रायपुर थाना क्षेत्र में युवती से रेप के मामले में मुख्य आरोपी को शुक्रवार को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। वहीं, नामजद दूसरे आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उसे फिलहाल कोर्ट में पेश नहीं किया गया। एसएसपी अजय सिंह ने शुक्रवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता में बताया कि कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती पीड़ित की हालत सामान्य है। पीड़िता से पूछताछकर उसके (धारा 180 बीएनएसएस) बयान दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष (धारा 183 बीएनएसएस) बयान दर्ज किए जाने के लिए आवेदन किया गया है। उन्होंने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अभिषेक के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसे शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया। मामले की जांच के लिए अलग–अलग टीम गठित की गई हैं। टीमों में दो महिला उप निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एसओजी और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन, घटना से संबंधित गवाहों से साक्ष्य जुटाने के लिए अलग से 04 तकनीकी टीमें बनाई गई हैं।

ये था मामला

रायपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को नशीला पदार्थ पिलाकर 19 वर्षीय युवती से रेप का मामला सामने आया था। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया है। केस दर्ज करने में देरी पर पीड़ित पक्ष के साथ पहुंची भीड़ ने देर शाम तक रायपुर थाने का घेराव किया।

गैंगरेप नहीं, रेप हुआ!

एसएसपी ने बताया कि घटनास्थल आस–पास के सीसीटीवी फुटेजों का अवलोकन करने पर मुख्य आरोपी अभिषेक 04 नंबर चक्की के पास खड़ा दिखाई दिया। दोपहर करीब 12 बजे वो पीड़िता को पैदल–पैदल मैजिक वाहन तक ले गया। यहां उसने पीड़ित को वाहन में बैठाया और किद्दूवाला में सूनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया। लगभग 02 घंटे बाद उसे वापस 4 नंबर चक्की लेकर पहुंचा। एसएसपी ने बताया कि मामले में नामजद अंकित और नाबालिग किशोर की घटना में शामिल होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

सीएम सिद्दरमैया की बढ़ी मुश्किलें, जारी रहेगी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

नई दिल्ली। मुडा की जमीन वापस करने के बावजूद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच रहेगी। वैसे ईडी सिद्दरमैया की पत्नी के नाम आवंटित किये गए 14 प्लॉट को जब्त करने से परहेज कर सकती है। माना जा रहा है कि जल्द ही ईडी इस मामले में सिद्दरमैया को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। ध्यान देने की बात है कि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद सिद्दरमैया की पत्नी पार्वती ने मुडा द्वारा आवंटित किए गए 14 प्लाट वापस कर दिये थे, जिसे मुडा ने स्वीकार भी कर लिया है।

गैरकानूनी तरीके से संपत्ति हासिल करने का अपराध

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) में साफ–साफ किसी भी गैरकानूनी तरीके से संपत्ति को हासिल करने को अपराध है और इसकी जांच के दौरान गैरकानूनी तरीके से संपत्ति हासिल करने (मनी लॉन्ड्रिंग) में शामिल सभी दोषियों के लिए सजा का भी स्पष्ट प्रविधान है।

भारत–कजाकित्सान के जवानों ने आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास किया

देहरादून। भारत और कजाकित्सान के जवानों ने शुक्रवार को उत्तराखंड के औली में आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास किया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच यहां 30 सितंबर से संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। यह संयुक्त अभ्यास काजिंद का आठवां संस्करण है। जहो सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड, औली में चल रहा है।

सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि आतंकवाद विरोधी अभियानों पर विशेष जोर देने के साथ भारतीय और कजाकिस्तान के बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से यह सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। इसमें 120 कर्मियों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन और भारतीय वायु सेना के साथ–साथ सहायक सेवाओं के जवानों द्वारा किया जा रहा है। दोनो सेनाओं की टुकड़ियों ने अब तक योग, आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन, रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग और स्पेशल हेलिबोर्न ऑपरेशन में भाग लिया है। योग सत्र ने दोनों टुकड़ियों के सैनिकों को शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक संतुलन और शारीरिक लचीलेपन को बढ़ावा देने में योग के महत्व को समझाया। भारतीय सैनिकों ने कजाकिस्तान दल के सामने आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन में अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिसमें हाथों–हाथ मुकाबला करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया।

विदेशी सैलानियों को लुभा रही देवभूमि की वादियां, 89% बढ़ी संख्या, तीन शहर बने पहली पसंद

देहरादून। देश के ऐतिहासिक स्थलों (खजुराहो, राजस्थान, ग्वालियर, ओरछा, बनारस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, उज्जैन आदि) के अलावा अब विदेशी सैलानियों को देवभूमि की वादियां भी लुभा रही हैं। तीन सालों में देवभूमि में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 89 प्रतिशत बढ़ी है। वर्ष 2023 में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 1.48 लाख है। सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों की आमद टिहरी, देहरादून और कोटद्वार में हुई है। दरअसल, भारत में अभी तक विदेशी सैलानियों की सबसे अधिक भीड़ ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में देखने को मिलती थी। लेकिन अब देवभूमि की शांत और सुरम्य फिजाएं भी उन्हें बुलाने लगी है। खासतौर पर पर्यटन के विभिन्न क्षेत्र (इको–पर्यटन, एयरो–पर्यटन, एस्ट्रो–पर्यटन) में वृहद विकास होने से विदेशी पर्यटक भी देवभूमि की शांत पहाड़ियों में सुकून तलाशने पहुंचने लगे हैं। पिछले सालों की अपेक्षा देवभूमि में आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में भारी उछाल आया है।

टिहरी पहुंचे 47,177 पर्यटक

समुद्र तल से दो हजार मीटर की उंचाई पर मौजूद टिहरी गढ़वाल पहाड़ी इलाके में स्थित एक जिला है। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती और धार्मिक स्थल पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। हाल ही में पर्यटन विभाग की ओर से यहां 1,293 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। टिहरी झील में हर साल वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन होता है, जहां भारी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। टिहरी में चंबा, बुढा केदार, कैंपटी फाल, देव प्रयाग और टिहरी बांध सहित कई स्थान पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। टिहरी में वर्ष 2021 में 2,300, 2022 में 22,709 और 2023 में 47,177 विदेशी सैलानी पहुंचे।

देहरादून जनपद में विदेशी सैलानियों की संख्या 90 प्रतिशत बढ़ी

देहरादून जनपद में ऋषिकेश और मसूरी पर्यटकों की पहली पसंद है। इसके अलावा देहरादून शहर में मौजूद बुद्धा मंदिर में भी पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है।

एससी–एसटी में उपवर्गीकरण का फैसला रद्द करने की उठी मांग

पुनर्विचार याचिका पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण की इजाजत देने वाले फैसले पर एक बार फिर अपनी मुहर लगा दी है। कोर्ट ने एससी–एसटी के उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले के विरुद्ध दाखिल दो दर्जन से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि फैसले में ऐसी कोई खामी नहीं है, जिसके लिए फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत हो। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की संविधान पीठ ने एक अगस्त के फैसले के विरुद्ध दाखिल थुमति रवि समेत विभिन्न पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करते हुए अपने 24 सितंबर के आदेश में यह बात कही।

शीर्ष अदालत ने खारिच की याचिकाएं

इसे शुक्रवार को अपलोड किया गया। शीर्ष अदालत ने उन याचिकाओं को भी खारिज कर दिया जिसमें पुनर्विचार याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने एक अगस्त को 6–1 के बहुमत से दिए फैसले में कहा था कि एससी–एसटी वर्ग के ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य एससी–एसटी वर्ग में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने 20 वर्ष पुराने पांच न्यायाधीशों के ईवी चिनैया (2004) मामले में दी गई व्यवस्था को गलत ठहरा दिया था। ईवी चिनैया फैसले में पांच न्यायाधीशों ने कहा था कि एससी–एसटी एक समान समूह वर्ग हैं और इनका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता।

सम्पादकीय

सड़कों का जाल

किसी भी देश और राज्य में विकास की रफ्तार उस स्थान की सड़कों की दशा पर निर्भर करती है। विकास का पहिया सड़कों के नेटवर्क से ही दौड़ता है जो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए सुलभ व्यवस्था उपलब्ध कराता है। उत्तराखंड में भी सड़कों के निर्माण और उसे दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाने के लक्ष्य में राज्य सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और भविष्य में इस लक्ष्य को और आगे तक ले जाने का संकल्प लिया गया है। हालांकि उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक वाले प्रदेश में सड़कों का निर्माण एक कठिन चुनौती है लेकिन तमाम बढ़ाओ के बावजूद सरकार ने सड़कों को हर उसे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया है जो विकास की रफ्तार में अपनी भागीदारी प्रदान करना चाहता है। धामी सरकार के तीन साल बेमिसाल के दौरान पीएमजीएसवाई में उत्तराखण्ड में कुल 1481 किमी लंबाई युक्त 519 सड़कों का निर्माण किया गया, जिस कारण 250 सौ से अधिक आबादी वाले 35 नए गांवों तक सड़क पहुंच पाई। इनमें वे क्षेत्र भी शामिल है जो काफी दुर्गम क्षेत्र में गिने जाते हैं और जहां सड़कों कब पहुंचना वहां के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। योजना के तहत वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में कुल 1481 किमी लम्बाई युक्त 519 नई सड़कों और 195 सेतुओं का निर्माण किया गया, वहीं पहले से निर्मित 159 किमी लंबी 61 ग्रामीण सड़कों का भी अपग्रेडेशन किया गया। इन सड़कों और पुलों के निर्माण पर कुल 2310 करोड़ रुपए व्यय किए गए। धामी सरकार में ही 250 से अधिक जनसंख्या की 35 बसावटों को सड़क से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाया गया है। युद्ध स्तर से किए गए कार्य का ही परिणाम है कि योजना के तहत प्रथम और दूसरे चरण के कार्य अब पूरे होने की स्थिति में पहुंच गए हैं, अब पीएमजीएसवाई तृतीय चरण के तहत पूर्व में निर्मित सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए 1824 करोड़ रुपए की स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है, इसके तहत कुल 2288 किमी लंबी सड़कों का अपग्रेडेशन किया जाना है। इस मानसून में उत्तराखंड की सड़कों का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है जिसे सरकार ने तत्काल निर्माण करते हुए इस यात्रा के लिए सुगम बनाया। अभी सरकार का लक्ष्य सड़कों के जाल को और आगे ले जाना है और इसी के तहत सड़क से वंचित आठ बसावटों को सड़क सम्पर्क से जोड़े जाने के लिए 119 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गई है। इसके बाद प्रदेश में 150 से कम जनसंख्या की कुल 1796 बसावटें ही ऐसी रह गई हैं, जहां सड़क नहीं पहुंच पाई है। राज्य सरकार जल्दी इन ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों को पहुंचाने का काम कर रही है जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र सरकार की बहुद्देशीय योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ना है। इस योजना में केंद्र सरकार के 90% अनुदान की मदद से अब तक उत्तराखण्ड में कुल 2329 सड़कों और 312 पुलों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। योजना पर अब तक कुल 10183 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसके फल स्वरूप 250 से अधिक जनसंख्या वाली 1846 बसावटों को सड़क से जोड़ा जा चुका है। सड़कों के निर्माण के दौरान उसकी गुणवत्ता और उसके टिके रहने की गारंटी महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा मॉनिटरिंग भी की जाती है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड के हर कोने तक सड़क पहुंचने का लक्ष्य सरकार ने रखा है और जिस गति से वर्तमान में धामी सरकार अपने संकल्पों को पूरा कर रही है उससे यह साफ है कि सरकार अपने लक्ष्य से अब ज्यादा दूर नहीं है।

क्या फिलिस्तीन शत्रु—राष्ट्र है?

संजय पराते

छत्तीसगढ़ एक बार फिर गलत कारण से चर्चा में है। छत्तीसगढ़ की पुलिस और प्रशासन के रवैए से और भाजपा सरकार की चुप्पी से यह प्रश्न खड़ा होता है कि हमारे देश और यहां के नागरिकों के लिए क्या फिलिस्तीन शत्रु—राष्ट्र है?

इससे पहले जून में छत्तीसगढ़ तब चर्चा में आया था, जब भाजपा सरकार के आने के तीन दिन बाद ही उत्तरप्रदेश से आए तीन पशु व्यापारियों और परिवहन कर्मियों की आरएसएस और भाजपा से जुड़े गौ—गुंडों ने हत्या कर दी थी। यह मॉब—लिंचिंग का नहीं, बल्कि हत्या का सुनियोजित मामला था। यह ऐसा मौका था, जब भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों को यह भरोसा दे सकती थी कि उसके राज में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं होगा और जाति—धर्म से परे सभी नागरिकों से समान व्यवहार होगा और कानूनी प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन इसके विपरित, सरकार द्वारा गठित एक एसआइटी के जरिए सभी मृतकों द्वारा आत्महत्या किए जाने का फर्जी निष्कर्ष निकालकर वास्तविक हत्यारों को बरी कर दिया गया। इस घटना का पूरे देश में विरोध हुआ था, लेकिन भाजपा और उसकी सरकार को कोई फर्क पडऩा नहीं था।

अब 16 सितंबर को ईद मिलादुन्नवी के दिन बिलासपुर में 5 मुस्लिम नौजवानों को घरों और मोहल्ले में फिलिस्तीन का झंडा लगाने के कथित अपराध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 197(2), जो देश की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कृत्यों से संबंधित है और जिसके लिए 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है, के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह घटना उस शहर में हुई है, जिसे छत्तीसगढ़ की न्यायधानी माना जाता है, क्योंकि प्रदेश का उच्च न्यायालय यहां पर है और इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि पूरी घटना उच्च न्यायलय के नाक के नीचे हुई है।ये गिरफ्तारियां संघी गिरोह से जुड़े लोगों और संगठनों की इस शिकायत के बाद की गई थी कि फिलिस्तीन का झंडा फहराने वाले लोग आतंकवादी हैं और ऐसा कृत्य देशद्रोह है। पूरे मामले को हिंदू बनाम मुस्लिम का बनाकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आग उगलने वाले वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल किए गए थे। धर्मनिरपेक्ष सोच रखने वाले नागरिक मंच के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय द्वारा किए गए कड़े प्रतिरोध के बाद जिला प्रशासन को गिरफ्तार युवकों को जमानत देने के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्मादी—हिंदू संगठनों के दबाव में गिरफ्तार युवकों को जेल में ही रखने की कोशिश में सिटी मजिस्ट्रेट 24 घंटों तक लुकाछिपी का खेल खेलते रहे और कानून की आंखों में धूल झोंकते रहे। ये उन्मादी संगठन मुस्लिमों को आतंकवादी बताकर उन्हें बिलासपुर (और छत्तीसगढ़) में न रहने देने तथा मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं को हथियार उठाने और अपनी रक्षा के लिए हिंदू समाज का सशस्त्रीकरण करने की गैर—कानूनी बात खुले तौर पर आम सभाओं में कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार के संरक्षण के चलते इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

यह एक उदाहरण है कि भाजपा शासित राज्यों में किस प्रकार मुस्लिम त्योहारों को भी उन पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही हमले मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में भी हुए हैं, हो रहे हैं। मोहर्रम के मौके पर इसी जुलाई में जम्मू—कश्मीर, बिहार, मध्यप्रदेश और झारखंड में भाजपा तथा विहिप नेताओं की शिकायतों पर यूएपीए तथा बीएनएस के अंतर्गत मामले दायर किए गए हैं, गिरफ्तारियां की गई है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती बातें फैलाकर समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का कोई भी मौका भाजपा छोडऩा नहीं चाहती। नफरती बातें करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां कचरे की टोकरी में पड़ा हुआ है और यहां का उच्च न्यायालय इन सब घटनाओं का मूकदर्शक बना हुआ है, जो पिछले एक दशक में न्यायपालिका के क्षेत्र में आई गिरावट का ही प्रतीक है।

पूरी दुनिया के लिए फिलिस्तीन आज राजनैतिक सवाल है। 20 सदी के अंत तक जहां दुनिया के तमाम पराधीन देश राजनैतिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, 21वीं सदी में आज भी फिलिस्तीन एक ऐसा देश है, जो अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए और इजरायल के प्रभुत्व से मुक्ति के लिए लड़ रहा है और जिसे दुनिया के उन सभी लोगों, समुदायों और संगठनों का समर्थन प्राप्त हैं, जो शांति, न्याय और आजादी के हक में है और यह समझते हैं कि फिलिस्तीन ठीक उसी प्रकार फिलिस्तीनियों का है, जिस प्रकार भारत भारतवासियों का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का, और जो इसीलिए फिलिस्तीनी भू—भाग को हड़प—हड़पकर वहां इजरायली बस्तियां बसाने की इजराइली सरकार की विस्तारवादी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इजरायल ने 1967 के बाद से फिलिस्तीन के पश्चिमी तट, गाजा पट्टी और पूर्वी येरूशलम पर कब्जा करके अपने भू—भाग का विस्तार किया है। फिलिस्तीनियों के हो रहे कत्लेआम के खिलाफ पूरी दुनिया में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में वे लाखों इजरायली नागरिक भी शामिल है, जो नेतन्याहू सरकार की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ हैं। भारत में भी बड़े पैमाने पर इजरायल और मोदी सरकार की इजरायलपरस्त नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। इजराइली सरकार इसे यहूदी बनाम मुस्लिम का मुद्दा बनाकर पेश कर रही है और इजरायल की इस मुहिम को अमेरिका और साम्राज्यवादी देशों का समर्थन मिल रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि अपनी मुस्लिम विरोधी नीतियों के कारण मोदी सरकार भी इजरायल और अमेरिका के साथ खड़ी हो गई है। मोदी सरकार का यह रुख फिलिस्तीन के मामले में हमारी स्वतंत्रता के बाद से अपनाए गए रुख से बिलकुल अलग है।

इस देश के लोगों ने अपने स्वाधीनता संघर्ष के दौर से ही फिलिस्तीन आंदोलन का समर्थन किया है। इस नीति को विकसित करने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के बाद यह हमारे देश की विदेश नीति का हिस्सा बनी, जिसे देश की किसी भी सरकार ने नकारने का साहस नहीं किया और जिसे हमारे देश के लोगों और लगभग सभी राजनैतिक पार्टियों की सहमति हासिल है। आज भी भारत सरकार की इस अधिकृत नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अघोषित रूप से इस नीति को इजराइलपरस्त बना दिया है। अब यह सरकार फिलिस्तिनियों से लडऩे के लिए इजरायल को हथियार उपलब्ध करवा रही है। इजराइल के लिए चेन्नई से हथियारों की खेप लेकर जा रहा एक जहाज स्पेन में पकड़ाया है। ये हथियार मेक इन इंडिया के तहत एक इजराइली कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम के जरिए अडानी द्वारा बनाए गए हैं। पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हुई है और इसके लिए केवल अडानी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह मामला बताता है कि देश के सार्वजनिक प्रतिरक्षा उद्योग का निजीकरण करने की कितनी बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ सकती है।

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस जुलाई महीने में ही अपने फैसले में चेतावनी दी है कि इस युद्ध में अगर कोई भी सहभागी पाया गया, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इजराइल को हथियार देकर फिलिस्तीनियों के कत्लेआम में मोदी सरकार भी शामिल हो गई है। इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को जब भी अमल में लाया जाएगा, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, जो इस देश की सर्वसम्मत नीति के खिलाफ देश की बेइज्जती कर रहे हैं।

इस 7 अक्टूबर को हमास—इजरायल युद्ध को एक वर्ष पूरे हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, इजरायल के हमलों में अभी तक लगभग 42000 फिलिस्तीन नागरिकों की मौतें हो चुकी हैं और मरने वालों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं और वे लोग हैं, जो इस युद्ध में किसी भी रूप में शामिल नहीं है, लेकिन जिन्हें इजरायली हमलों के कारण अपने जीवन की रक्षा करने के लिए बार—बार विस्थापित होना पड़ा है।

इजरायल ने फिलिस्तीन इलाकों में स्कूलों, अस्पतालों, शरणार्थी शिविरों और आबादी इलाकों में अनगिनत बर्बर हमले किए हैं। इन हमलों के कारण 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा है। जून माह के मेडिकल जर्नल द लांसेट के अनुसार, मरने वालों की वास्तविक संख्या 1.86 लाख से ज्यादा हैं। उसका कहना है कि हर एक प्रत्यक्ष मौत के साथ 4 अप्रत्यक्ष मौतें भी जुड़ी हुई हैं, जो इस युद्ध के कारण उत्पन्न परिस्थितियों : जैसे संक्रमक रोग, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की बर्बादी, भोजन, पानी और आवास की कमी तथा पलायन आदि : से जुड़ी हैं। ये हमले सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कायदे—कानूनों का खुला उल्लंघन है और पूरी दुनिया में यह मांग जोर पकड़ रही है कि फिलिस्तीनियों के इस कत्लेआम के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध अपराधी घोषित किया जाए। सभी जानते हैं कि हिटलर द्वारा यहूदियों के कत्लेआम के लिए सभी जिम्मेदारों पर मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दी गई थी और यह मुकदमा इतिहास में न्यूरेम्बर्ग ट्रायल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है।जिस हमास को आज इजरायल और अमेरिका आतंकवादी संगठन बता रहा है, उस हमास को खुद उन्होंने फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा को खत्म करने के लिए बढ़ावा दिया था। बाद में यह संगठन फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई में वहां की जनता का राजनैतिक समर्थन प्राप्त करने में सफल हुआ। लेकिन अब हमास के बहाने से फिलिस्तीन की समूची जनता को आतंकवादी ठहराने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रकार, हिजबुल्ला लेबनान की जनता के बीच मान्यताप्राप्त राजनैतिक संगठन है, जिसे आतंकवादी और फिलिस्तीन—समर्थक बताते हुए इजरायल आज लेबनान पर हमले कर रहा है। इसी तर्क का विस्तार भाजपा आज भारत में कर रही है और कह रही है कि जो फिलिस्तीन के साथ हैं, वे सब आतंकवादी हैं। लेकिन यह ठीक वैसा ही तर्क होगा, जैसे भाजपा को वोट देने वाली समूची जनता को सांप्रदायिक कहना।

संघी गिरोह की भारत में मुस्लिमों से जन्मजात दुश्मनी जगजाहिर है। फिलिस्तीन के स्वाधीनता संग्राम के साथ भी कभी उसकी हमदर्दी नहीं रही, क्योंकि संघी गिरोह ने शुरू से ही साम्राज्यवाद के प्रति अपनी स्वामीभक्ति दिखाई है और अब मोदी सरकार ने तो सत्ता में आने के बाद अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी को खुश रखने की नीति को व्यवहारिक रूप देना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि अब वह संयुक्त राष्ट्र संघ में भी खुलेआम इजरायल का समर्थन कर रहा है। यह नीति गुट निरपेक्षता की नीति का अघोषित परित्याग है।

तो क्या अब भारत की जनता को भाजपा और संघी गिरोह की इजरायलपरस्त नीति को मान लेना चाहिए? हमारे देश का संविधान अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इसमें राजनैतिक अभिव्यक्ति का अधिकार भी शामिल है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए भारत का कोई भी नागरिक, समुदाय और संगठन विदेश नीति के मामले में भी केंद्र सरकार की उन नीतियों/फैसलों का विरोध कर सकता है, जिसके बारे में वे यह मानते है कि यह देश के व्यापक हितों और मानवीय संवेदना के खिलाफ है। जब किसी भी देश में लाखों निदोष लोगों का कत्लेआम किया जा रहा हो और हमारे देश की सरकार मौन हो, इसके खिलाफ आवाज उठाने और मानवता के हक में बात करने का अधिकार संविधान देता है। फिर फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन जताना, वहां हो रहे कत्लेआम पर आंसू बहाकर दुख का इजहार करना और फिलिस्तीनी झंडे फहराना देश के किसी कानून का उल्लंघन कैसे हो सकता है? जब पूरी दुनिया में ईद का त्योहार मनाया जा रहा था, तो ईद की खुशी में फिलिस्तीनियों के कत्लेआम का गम भी शामिल था और मानवीय संवेदना के साथ लोग इस गम का भी इजहार कर रहे थे।

अब फिर वही सवाल : क्या फिलिस्तीन शत्रु राष्ट्र है? भारत सरकार का आधिकारिक रुख तो यही है कि फिलिस्तीन हमारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन प्रदेश में पुलिस के एक उच्च पदाधिकारी ने मीडिया को बयान दिया है कि उसने फिलिस्तीनी झंडे फहराने वाले युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब यह तय करने का अधिकार अदालत को है। तो अब सवाल यह भी बनता है कि इस देश की विदेश नीति और कौन—सा देश मित्र राष्ट्र होगा और कौन—सा शत्रु राष्ट्र, यह तय करने का अधिकार केंद्र सरकार ने संसद से छीनकर प्रशासन और अदालत को सौंप दिया है? क्या हमारी पुलिस, हमारे प्रशासन और देश के संघीय ढांचे के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की भी, न्यूनतम अक्लमंदी मारी गई है? यह कानून के दुरुपयोग का और मुस्लिम समुदाय को उसकी राजनैतिक अभिव्यक्ति के लिए उत्पीड़ित करने, उन्हें डराने—धमकाने का सीधा मामला बनता है।

लेकिन यह गड़बड़झाला क्यों? दरअसल, भाजपा के मोदी राज ने सरकार और पार्टी का बारीक अंतर मिटाने की सुनियोजित कोशिश की है। यह स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि अब भाजपा ही सरकार है और सरकार ही भाजपा है। भाजपा की नीतियों को ही सरकार की नीतियों के रूप में दिमाग में बैठाने की कोशिशों का नतीजा यह है कि पुलिस और प्रशासन के विभिन्न हलकों में भाजपा की नीतियों का अंधानुकरण करने और पार्टी नेताओं तथा हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की इच्छानुसार काम करने की प्रवृत्ति पैदा हुई है। बिलासपुर की घटना में पुलिस और सरकार का रूख यही बताता है कि संविधान के मूल्यों और उसकी भावना को खत्म करने और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए कानून को तोडऩे—मरोडऩे का काम ऊंचे स्तर से ही जोर—शोर से जारी है। देश की एकता—अखंडता पर खतरा मंडरा रहा है और यह खतरा भाजपा और संघी गिरोह की ओर से आ रहा है।

राजनैतिक दलों के बिगड़े बयान, क्यों? कैसे रुके?

अजय दीक्षित

इधर कुछ दिनों से भारत के राजनैतिक दल एक दूसरे के हर काम की समीक्षा करते हुए दूसरे दलों की आलोचना करते हैं । यह ऐसा ही है मानों हम अपने पड़ौसी के घर बने खाने की ताक—झांक करते हैं और कहें कि इन्होंने भिण्डी की सब्जी क्यों बनाई? या इन्होंने दाल मसूर की क्यों बनाई? अब यह आपके पड़ौसी के घर का मामला है, आपको इससे क्या लेना ! अब आतिशी के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने पर कांग्रेस और अन्य दल अनेक प्रकार की बयानबाजी कर रही है । अभी लोकसभा चुनाव में आप पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था । कन्हैया कुमार तो सुनीता केजरीवाल से भी मिला था । विगत सम्बन्धों को देखते हुए कुछ तो संयम और मर्यादा बरतनी चाहिए । भाजपा के प्रवक्ता तो अब जरा जरा सी बात पर सभी गैर भाजपा पार्टी पर बिफर पड़ते हैं । अरे, अगर भाजपा को दिल्ली जीतनी है तो जनता के पास जायें । पिछले दो चुनाव में कांग्रेस को तो दिल्ली विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली और भाजपा को एक बार मात्र तीन और दूसरी बार छः या सात सीटें मिलीं । असल निर्णायक जनता होती है । शायद भाजपा के प्रवक्ता समझते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियों की आलोचना करने पर मोदी जी खुश हो जाएंगे । आजकल संबित पात्रा नहीं दिखलाई पड़ते । 2019 के लोकसभा चुनाव में वे पुरी(उड़ीसा) से हार गये थे । इस बार जीत गये परन्तु इसका बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस की महिला प्रत्याशी ने चुनाव के लिए प्रचार किया ही नहीं । उन्होंने अपना नाम भी वापस नहीं लिया और चुनाव लड़ा भी नहीं । शायद संबित पात्रा उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनना चाहते हों या केन्द्रीय मंत्रिमंडल में जगह । अब भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आतिशी के माता—पिता अफजल गुरु का साथ दे रहे थे । अब अफजल गुरु की फांसी को मेहबूबा मुफ्ती भी ग़लत बतलाती हैं जिसके साथ भाजपा ने मिलकर कश्मीर में सरकार बनाई थी ।

इधर राहुल गांधी के बारे में भाजपा प्रवक्ता, महाराष्ट्र के मंत्री आदि ऐसी—ऐसी बातें कह रहे हैं जो कानून का खुला उल्लंघन है । परन्तु इस पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कुछ नहीं बोल रहा है । स्वयं स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस को भी उनके गणेश पूजन पर भी आपत्ति है । असल में मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री गणेश उत्सव पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर गये थे । वहां शायद पूजन चल रहा होगा तो उन्होंने उस पर भाग ले लिया । इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है । असल प्रश्न है प्रशासन और जुडीशियरी का अलग—अलग रहना । कोई यह नहीं कह रहा है कि प्रधानमंत्री कहीं जा नहीं सकते । वे देश के सवोच्च नेता हैं । उन पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता । परन्तु अच्छा होता कि मुख्य न्यायाधीश के घर न जाकर उनसे कहीं और किसी मीटिंग में मिल लेते । अब कहते हैं कि मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में भी तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गये थे । शायद यह भी ठीक नहीं कहा जा सकता । अपना नाम घोषित नहीं करने की शर्त पर अनेक रिटायर्ड जजों का कहना है कि चाहे शिष्टाचारवश ही क्यों न हो जुडिशरी और प्रशासन के मुख्य प्रमुख गैर सार्वजनिक अवसरों पर न मिलें ।

बेबी जॉन से वरुण धवन का धांसू पोस्टर आउट, सलमान खान ने शुरू की फिल्म की शूटिंग

बॉलीवुड स्टार वरूण धवन की अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन है जिसे जवान के डायरेक्टर एटली निर्देशित कर रहे हैं. इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं और मेकर्स भी फिल्म की अपडेट शेयर करते रहते हैं. अब हाल ही में फिल्म से नया धांसू पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें वरूण किलर लुक में नजर आ रहे हैं. वहीं मेकर्स ने फिल्म से सलमान के कैमियो के बारे में भी अपडेट शेयर की है.ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा— बेबी जॉन की झलक, मास सिनेमा अपने बेस्ट लेवल पर. सलमान खान ने इस वीकेंड में अपना

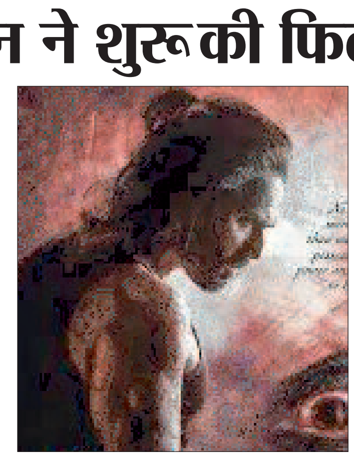

कैमियो शूट किया. वरुण धवन को एक अलग ही मास अवतार में और बेबीजॉन की 5 मिनट से अधिक की झलक देखने के लिए उत्सुक था मैंने जो देखा वह बिल्कुल शानदार है. आखिरकार जवान के बाद एटली के टैलेंट पर कौन शक कर सकता है. और सभी फैस के लिए सलमान खान इस वीकेंड के आखिरी में अपने हिस्से की शूटिंग करने के लिए तैयार हैं. बेबी जॉन इस क्रिसमस पर आ रही है 25 सितंबर से सिनेमाघरों में.

बेबी जॉन की स्टोरी को कलीश ने लिखा और डायरेक्ट किया है. बेबी जॉन एटली के निर्देशन में बनी फिल्म थेरी का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है. थेरी साल 2016 में रिलीज हुई थी, जिसमें साउथ सुपरस्टार विजय और सामंथा रुथ प्रभु ने लीड रोल प्ले किया था.

कार्तिक आर्यन की सबसे बड़ी नॉन थिएट्रिकल डील

कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित स्टारर अनीस बज्मी निर्देशित हॉरर कॉमेडी, भूल भुलैया 3 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का टीजर लॉन्च किया है जिस पर फैंस का शानदार रिएक्शन देखने को मिला है. अब हाल ही में पता चला है कि भूषण कुमार ने भूल भुलैया 3 के लिए एक बड़ी नॉन—थिएट्रिकल डील तय की है. जो इस फ्रेंचाइजी और कार्तिक आर्यन के लिए अब तक की सबसे बड़ी डील है. रिपोर्ट्स के मुताबिक भूल भुलैया 3 के डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स 135 करोड़ रूपये में बेचे गए हैं. भूल भुलैया 2 की सफलता के बाद नेटफ्लिक्स ने डिजिटल राइट्स के लिए मोटी रकम हासिल की है, लेकिन सैटेलाइट राइट्स सोनी नेटवर्क के पास हैं. दूसरी ओर टीम म्यूजिक से बड़ा मुनाफा कमाने के लिए एक्साइटेड है. क्योंकि एल्बम में 4 सुपर—हिट गाने हैं.

पाकिस्तान के मैच में बवाल, रुमाल ने दिलाया बल्लेबाज को जीवनदान

नईदिल्ली, वुमेन्स टी—20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया. इस मैच में एक रुमाल के चक्कर में बल्लेबाज को नॉट—आउट करार दिया, जिसके चलते बवाल मच गया है. बात कुछ ऐसी थी कि गेंद फेंकी गई, बल्लेबाज को आउट भी करार दिया गया, लेकिन फिर तुरंत ही अंपायर ने अपना फैसला बदला और बल्लेबाज को नॉटआउट दिया गया. आइए आपको इस मामले के बारे में विस्तार से बताते हैं. पाकिस्तान के दिए 117 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी. इसी बीच 13वां ओवर लेकर आईं पाकिस्तान की नाशरा संधु, जिनके सामने क्रीज पर

मौजूद थीं निलाक्षी डी सिल्वा. नाशरा ने गेंद फेंकी, लेकिन उस दौरान उनका रुमाल गिर गया.वहीं, निलाक्षी ने स्वीप करना चाहा, लेकिन वह गेंद को मिस कर गईं और अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया. लेकिन, बल्लेबाजों की ओर से रुमाल गिरने की शिकायत की गई. मामला थर्ड अंपायर तक पहुंचा, जहां इस बॉल को डेड बॉल करार दिया गया और निलाक्षी को जीवनदान मिल गया. हालांकि निलाक्षी 25 गेंद पर 22 रन बनाकर आउट हुईं.

पाकिस्तान—श्रीलंका के बीच खेले गए मैच के दौरान हुए इस रुमाल विवाद पर क्रिकेट गलियारों में चर्चा जारी है. एमसीसी के नियम में क्लॉज 20.4.2.6 के अनुसार, अगर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज का ध्यान गेंद खेलने से पहले किसी आवाज या किसी मूवमेंट या फिर किसी और वजह से भंग होता है तो उस गेंद को अंपायर डेड करार दिया जाता है. इस मामले में रुमाल गिरने से बल्लेबाज निलाक्षी का ध्यान भटका, इसलिए इस गेंद को डेड करार दिया गया.

विजय की आखिरी फिल्म थलापति 69 से आया बड़ा अपडेट, बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल की हुई एंट्री

थलापति 69 साउथ सुपरस्टार विजय की आखिरी फिल्म हो सकती है इसीलिए फैंस इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं. इसी के साथ मेकर्स भी आए दिन फिल्म से नया अपडेट शेयर करते हुए फैंस की एक्साइटमेंट बरकरार रख रहे हैं. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म की कास्ट रिवील की है. तो आइए जानते हैं थलापति की फिल्म में किस बॉलीवुड एक्टर ने एंट्री ली है. थलापति 69 के मेकर्स ने बड़ा अपडेट शेयर करते हुए बताया कि फिल्म में बॉबी देओल की एंट्री हो चुकी है. हालांकि उनका रोल क्या होगा अभी इस बारे में खुलासा नहीं हुआ है. केवीएन प्रोडक्शन ने हाल ही

में एक धांसू पोस्टर शेयर किया जिसमें बॉबी देओल का फेस रिवील किया गया. पोस्टर के साथ मेकर्स ने कैप्शन लिखा— 100त्न ऑफिशियल, हम बहुत खुश और एक्साइटेड हैं अनाउंस करते हुए कि बॉबी देओल ने थलापति 69 की कास्ट जॉइन कर ली है. थलापति 69 में बॉबी देओल की एंट्री से फैंस काफी खुश हो गए हैं सबने कमेंट सेक्शन में अपनी खुशी जाहिर की. एक ने लिखा— वाह थलापति विजय और बॉबी देओल, स्क्रीन पर धमाका होगा. एक ने कमेंट किया— वाव बड़े पर्दे पर धमाका होगा. एक ने लिखा—थलापति का लुक कब सामने आएगा, अब इंतजार नहीं हो रहा. केवीएन प्रोडक्शंस ने थलापति 69 को प्रोड्यूस किया है जिसे तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज किया जाएगा. प्रोडक्शन हाउस ने हाल ही में फिल्म का पोस्टर भी रिलीज किया और टैगलाइन के साथ इसकी डिटेल की अनाउंसमेंट की.

शारजाह में स्पिन चुनौती का सामना करने ऑस्ट्रेलिया की टीम में लिचफील्ड की वापसी की उम्मीद

नई दिल्ली, युवा बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड, जो कमर दर्द के कारण दोनों अभ्यास मैचों से बाहर रहीं, के शनिवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के महिला टी20 विश्व कप के पहले मैच के लिए फिट होने की उम्मीद है। क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू के अनुसार, 21 वर्षीय लिचफील्ड ने गुरुवार को अपनी टीम की साथियों के साथ प्रशिक्षण लिया और चयन के लिए उपलब्ध होने की राह पर हैं लिचफील्ड ने कहा, अभ्यास मैचों को मिस करना कठिन रहा है, लेकिन अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूं। मैं मैदान पर वापस आने और टीम में योगदान देने के लिए उत्साहित हूं। ऑस्ट्रेलिया ने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में कभी नहीं खेला है, और शनिवार के मैच से पहले उन्हें इस स्थल पर प्रशिक्षण का अवसर नहीं मिला।

ओडिशा एफसी ने केरला ब्लास्टर्स एफसी को 2—2 के ड्रा पर रोका

भुवनेश्वर, ओडिशा एफसी ने गुरुवार को अपने घरेलू मैदान कलिंगा स्टेडियम में खेले गए इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2024—25 मुकाबले में पिछडऩे के बाद शानदार वापसी करते हुए केरला ब्लास्टर्स एफसी को 2—2 की बराबरी पर रोककर एक—एक अंक बांट लिया। रोमांचक मैच में केरला ब्लास्टर्स की ओर से मोरोक्कन विंगर नौहा सदौई ने 18वें और स्पेनिश स्ट्राइकर हेसुस जिमेनेज ने 21वें मिनट में गोल दागे जबकि ओडिशा एफसी की तरफ से केरला ब्लास्टर्स के फ्रेंच डिफेंसिव मिडफील्डर एलेक्जेंडर कोएफ़ ने 29वें मिनट में आत्मघाती गोल और ब्राजीली स्ट्राइकर डिएगो मौरिसियो ने 36वें मिनट में गोल किए। नौहा सदौई को पहला गोल करने और दूसरे में सहायता प्रदान करने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज जगरनॉट्स द्वारा वापसी करके ड्रा खेलने स्पेनिश हेड कोच सर्जियो लोबेरा निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। ओडिशा एफसी चार मैचों में एक जीत, एक ड्रा और दो हार से चार अंक लेकर तालिका में दसवें से नौवें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं, ब्लास्टर्स द्वारा दो गोल की बढ़त गंवाकर ड्रा खेलने से स्वीडिश हेड कोच मिकेल स्टेहरे जरूर निराश होंगे। केरला ब्लास्टर्स एफसी चार मैचों में एक जीत, दो ड्रा और एक हार से पांच अंक लेकर तालिका में पांचवें से चौथे स्थान पर आ गए हैं। मैच का पहला गोल 18वें मिनट में आया, जब मोरोक्कन लेफ्ट विंगर नौहा सदौई ने केरला ब्लास्टर्स को शुरुआती बढ़त दिलाते हुए स्कोर 1—0 कर दिया। स्पेनिश स्ट्राइकर हेसुस जिमेनेज ने सेंट्रल चैनल से बॉक्स के अंदर घुसने के बाद अपने बायीं तरफ छोटा सा थ्रू—पास दिया, जिस पर पीछे से दौडक़र पहुंचे नौहा ने पहले ही टच पर करारा राइट फुटर शॉट लगाकर गेंद को टॉप राइट कॉर्नर के अंदर गोल जाल में उलझा दिया जबकि ओडिशा एफसी के गोलकीपर अमरिंदर सिंह अपने बायीं तरफ डाइव लगाने के बावजूद बचाव करने में नाकाम रहे।

एक नजर

मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा ठेकेदारों का कार्यबहिष्कार

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर डटे ठेकेदारों ने मांगें पूरी नहीं होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखने की चेतावनी दी है। कहा कि पर्वतीय ठेकेदार संघ समिति मांगों को लेकर पिछले कई माह से संघर्ष कर रही है। यदि जल्द मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ठेकेदार उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे।

शुक्रवार को आयोजित बैठक में ठेकेदरों ने कहा कि बड़ी निविदाओं से बाहरी राज्यों के ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय ठेकेदारों के हित को देखते हुए निविदाओं को छोटा किया जाना चाहिए, जो अतिरिक्त रायल्टी बढ़ाई गई है उसे निरस्त किया जाना चाहिए, पंजीकरण का सरलीकरण किया जाना चाहिए। कहा कि आपदा एवं अन्य लंबित देयकों की रायल्टी शीघ्र दी जानी चाहिए। इस मौके पर भाष्कर बड़थ्वाल, भरत सिंह नेगी, प्रभात रावत, राकेश काला, दिनेश रावत, पूरण सिंह रावत, विजय नेगी, विनोद बिष्ट, विनोद जखमोला, मनोज रावत, अरविंद बंसल, शिवम बंसल, पदम गुप्ता, अनिल नेगी, चंद्र मोहन आदि मौजूद रहे।

प्रयोगशाला सहायक 15 अक्टूबर को रहेगें अवकाश पर

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थलीसैंण के प्रयोगशाला सहायकों ने शुक्रवार को तीन सूत्री मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर आक्रोश जताया। कहा कि कर्मचारी 5 अक्तूबर तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इसके बाद 15 अक्तूबर को प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों में प्रयोगशाला सहायक एक दिन के अवकाश पर रहेंगे। यदि इसके बावजूद मांगों पर कदम नहीं उठाएं जाते तो आंदोलन की आगे की रणनीति बनाई जाएगी। थलीसैंण डिग्री कॉलेज में तैनात प्रयोगशाला सहायक धमेंद्र रावत ने कहा कि प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय डिग्री कॉलेजों में प्रयोगशाला सहायक की पदोन्नति ढांचे का स्टाफिंग पैटर्न का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने, प्रयोगशाला सहायकों की शैक्षिक योग्यता उच्चीकृत करने और 2013 में स्वीकृत 2400 ग्रेड पे 1 जनवरी 2006 से लागू करने जैसी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। बीते लंबे समय से प्रयोगशाला सहायक अपनी मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

निबंध प्रतियोगिता में भाष्कर और प्रीति ने मारी बाजी

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : वन विभाग धुमाकोट दीवा रेंज और सिविल सोयम स्यूंसी रेंज के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को जनता इंटर कॉलेज ग्वीनखाल में वन्य प्राणी सुरक्षा पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में भाष्कर रावत प्रथम, आयुष नेगी द्वितीय, और प्रिंस कुमार तृतीय स्थान पर रहे। सीनियर वर्ग में प्रीति ने प्रथम, रश्मि ने द्वितीय और प्रिय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सभी विजेताओं को वन विभाग द्वारा पुरस्कृत किया गया। यह कार्यक्रम एक अक्तूबर से शुरू हुए वन्य प्राणी सप्ताह के तहत आयोजित किया गया। जिसमें विभागीय कर्मचारियों ने छात्रों के बीच वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैलियां निकालीं और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। गोष्ठी के दौरान सिविल सोयम स्यूंसी रेंज के वन दरोगा शिव सिंह रावत ने छात्रों को वन्य जीवों के संरक्षक बनने की शपथ दिलाई। उन्होंने बाघों की घटती आबादी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

डा. नैथानी को स्वच्छता प्रहरी सम्मान मिलने पर जताई खुशी

श्रीनगर गढ़वाल : नगर निगम श्रीनगर की ओर से स्वच्छता ही सेवा-2024 अभियान के तहत स्वच्छता प्रहरी सम्मान समारोह में स्वच्छता ब्रान्ड एम्बेसडर डॉ. बीपी नैथानी, व्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष वासुदेव कण्डारी, डॉ. विनीत पोस्ती, हरि सिंह बिष्ट, आनन्द भण्डारी आदि को सम्मानित किए जाने पर बार एसोसिएशन श्रीनगर के सदस्यों ने खुशी जाहिर की है। बार एसोसिएशन श्रीनगर के संरक्षक अनूप श्री पांथरी ने कहा कि डॉ. बीपी नैथानी एवं मंजू नैथानी द्वारा विगत 10 वर्षों से चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर लोगों में भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है। डा. नैथानी सहित आदि के सम्मानित होने पर उत्तराखंड काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदस्य अर्जुन सिंह भंडारी, संरक्षक अनूप श्री पांथरी,पूर्व सचिव विकास पंत, देवी प्रसाद खरे, बलबीर सिंह रौतेला, ओम प्रकाश मैठाणी, आनन्द सिंह बुटेला, नितेश भारती आदि ने खुशी जाहिर की है। (एजेंसी)

जल्द पूरा करें मालन पुल मरम्मत कार्य

अपर सचिव धीराज गर्ब्याल ने किया मालन पुल का निरीक्षण

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : अपर सचिव धीराज गर्ब्याल ने मालन पुल मरम्मत कार्य का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कहा कि जनता के हित को देखते हुए जल्द से जल्द पुल मरम्मत कार्य पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने सड़कों की मरम्मत पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए।

शुक्रवार को कोटद्वार पहुंचे अपर सचिव ने कोटद्वार से भाबर को जोड़ने वाले मालन पुल मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि विशेषों की टीम की निगरानी में पुल मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि पुल मरम्मत में किसी भी तरह की कमी न रहें। उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर पुल मरम्मत कार्य का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। कहा कि हमारा लक्ष्य जल्द से जल्द पुल मरम्मत कर इसे जनता के आवागमन के लिए खोलना है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता निर्भय सिंह को सड़क मरम्मत कार्य करवाने के भी निर्देश दिए। कहा कि कई स्थानों पर शहर की सड़कें बदहाल पड़ी हुई हैं। ऐसे में आवागमन करने वालों को खतरा बना रहता है। लोक निर्माण विभाग जल्द से जल्द बदहाल सड़कों को चिह्नित कर उनके मरम्मत कार्य को प्रांरभ करवाएं।

अपर सचिव धीराज गर्ब्याल ने मालन पुल मरम्मत कार्य का निरीक्षण करते हुए।

भगवान राम व लक्ष्मण ने किया राक्षसों का वध

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : दुगड्डा में चल रही रामलीला के चौथे दिन भगवान राम व लक्ष्मण द्वारा राक्षसों के वध का मंचन किया गया। रामलीला देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। पूरा पंडाल जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा।

रामलीला के चौथे दिन का शुभारंभ बलूनी क्लासेस की मैनेजिंग डायरेक्टर अभिलाषा भारद्वाज ने दीप प्रज्जवलित कर किया। मंचन के दौरान धरती पर राक्षसों का प्रकोप बढ़ गया। वनों में कोई ऋषि मुनि यज्ञ तपस्या भी नहीं कर पा रहा है। चारों और राक्षसों के अत्याचार कर रहे थे। ऋषि विश्वामित्र भी अब अनुष्ठान नहीं कर पा रहे थे। राक्षसों के बढ़ते प्रकोप से तंग आए विश्वामित्र अयोध्या पहुंचते हैं और राजा दशरत से धर्म की रक्षा हेतू राम और लक्ष्मण मांगते हैं। इसके बाद राम लक्ष्मण यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का वध करते हैं। इसके बाद ताड़िका वध का भी मंचन किया गया। इस मौके पर प्रदीप बड़ोला, संजव कोटनाला, बबली बिष्ट, राहुल जैन, वीरेंद्र शाह, नरेंद्र शहनाई, शिवचंद्र, पुष्कर, मुकेश काला, अमन जैन, विनायक आदि मौजूद रहे।

दुगड्डा में आयोजित रामलीला के दौरान मंचन करते कलाकार

पेंसनर्स के हित में काम करें सरकार

जयन्त प्रतिनिधि

कोटद्वार : गवर्नमेंट पेंसनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पेंसनर्स की अनदेखी होने पर रोष व्यक्त किया है। इस दौरान एसोसिएशन ने गोल्डन कार्डधारकों को ओपीडी व दवाई भी निःशुल्क देने की मांग की है। कहा कि पेंसनर्स के हित को देखते हुए सरकार को गंभीरता से कार्य करना चाहिए। एसोसिएशन के अध्यक्ष जयवीर सिंह रावत व चंद्रप्रकाश नैथानी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। बताया कि राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले सेवकों को दस माह के वेतन का समतुल्य राशि एक मुश्त प्रदान की जाती है। वर्ष 1987 से इसकी कटौती संबंधित सेवक की पेंशनराशि से 15 वर्ष यानी 180 माह तक की जाती है। उस समय प्रचलित व्याज की दर 12 प्रतिशत से अधिक होने के अनुसार कटौती की अवधि आंकलित की गई थी। जबकि, वर्तमान ब्याज दर तीन प्रतिशत से लेकर वरिष्ठ नागरिकों को 6.8 प्रतिशत है। वर्तमान व्याज दर आंकलन करने से संपूर्ण राशिकरण की राशि की वसूली दस वर्ष आठ माह यानि अधिकतम 11 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। जबकि वसूली 15 वर्ष तक की जा रही है। प्रकाश में आया है कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश केरल में उच्च न्यायालय के दरवाजे कर्मचारी संगठनों द्वारा खटखटाये गए और कई प्रदेशों ने 11 वर्ष पूर्ण होने पर राशिकरण की राशि की कटौती पर तत्काल रोक लगा दी है। वहीं, सेवानिवृत्त एवं परिवारिक पेंशन पाने वाले कर्मचारी से भी गोल्डन कार्ड कटौती की दरें सेवारत कर्मचारियों के समान है। जबकि, सेवारत कर्मचारी के कम से कम चार लाभार्थी इससे आच्छादित हैं और पेंशनर की पेंशन आधी और लाभार्थी की संख्या केवल दो ही है। सामान्यत वृद्धजनों की गंभीर बीमारियों में भी शल्य चिकित्सा संभव नहीं होती है। अतः सामान्य बीमारियों में गोल्डन कार्ड धारक को ओपीडी व दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएं। साथ ही स्वास्थ्य प्राधिकरण में सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के स्थान पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। इस मौके पर श्याम प्रसाद कोटनाला, प्रवेश नवानी, रघुवीर सिंह रावत, हरीश मैंदोला, महेंद्र नेगी, वाचस्पति बहुखंडी, वीरेंद्र रावत, सुधीर असवाल आदि मौजूद रहे।

पूर्व सैनिकों ने उठाई योजना ने छूट देने की मांग

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : पूर्व-सैनिक सेवा परिषद ने सौर ऊर्जा स्कीम में छूट देने की मांग की है। कहा कि योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम दो लाख रुपये जमा करने पड़ रहे हैं। जिससे सामान्य व गरीब परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है। इस संबंध में परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण बड़थ्वाल ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि विद्युत की भारी जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार सौर ऊर्जा स्कीम लेकर आई है। लेकिन, इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए परिवारों को दो लाख रुपये जमा करवाने है। बताया कि सामान्य व गरीब परिवारों के पास इतनी बड़ी रकम की एक साथ व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए सरकार को पूर्व सैनिक व गरीब परिवारों के लिए स्कीम में थोड़ा और छूट देनी चाहिए। इस मौके पर सीपी डोबरियाल, बलवंत सिंह रावत, देवेंद्र नेगी, सीपी धूलिया, संजय असवाल, अनूप बिष्ट आदि मौजूद रहे।

श्रमिकों का मेहनताना नहीं देने वाला फैक्ट्री स्वामी गिरफ्तार

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : कई माह तक फैक्ट्री में कार्य करवाने के बाद श्रमिकों का मेहनताना न देने वाले फैक्ट्री मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।

इस संबंध में कुछ दिन पूर्व श्रमिकों ने कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि वह जशोधरपुर कोटद्वार में स्थित हिमगिरी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में कार्य करते थे। लेकिन, फैक्ट्री स्वामी ने उन्हें कई वर्षों मेहनताना नहीं दिया है। फैक्ट्री स्वामी पर श्रमिकों का करीब साल लाख 35 हजार रुपये बकाया है। मेहनताना मांगने पर श्रमिकों को डराया व धमकाया जाता था। जिससे श्रमिकों के समक्ष आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया था। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी थी। मामले में फैक्ट्री स्वामी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद थाना बजरिया निकट देवी मंदिर निवासी शान मलिक उर्फ शान ए आजम पुत्र बूंदु मलिक को उसके घर से गिरफ्तार कर कोटद्वार लाया गया।

कोटद्वार पुलिस हिरासत में फैक्ट्री स्वामी

विद्यार्थियों को दी जंगली जानवरों की जानकारी

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैंसडौन की ओर से वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को कार्बेट ग्लैक्सी फिल्म के माध्यम से हाथी व पक्षियों के बारे में बताया गया।

सरस्वती विद्या मंदिर काशीरामपुर तल्ला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्बेट ग्लैक्सी फिल्म के माध्यम से विद्यार्थियों को हाथी व पक्षियों के स्वभाव और विभिन्न प्रजातियोगियों के बारे में बताया गया।

पक्षी विशेषज्ञ व वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट आफ ग्रीन कोरिडोर चैंपियन राजीव बिष्ट ने कहा कि धरती पर पर्यावरण का एक बहुत बड़ा महत्व है। हमें अपने जंगलों में रहने वाले प्रत्येक जानवर की प्रजाति व उनके स्वभाव के बारे में पता होना चाहिए। इस मौके पर सहायक वन संरक्षक अनामिका, सहायक वन संरक्षक सोनानदी अनामिका, वन दरोगा रवींद्र देवी, रामकरन, कल्पेश्वर, प्रिया, शारदा आदि मौजूद रहे।

आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते विद्यार्थी

शिविर आठ अक्टूबर को

जयन्त प्रतिनिधि ।कोटद्वार : विकासखंड दुगड्डा के अंतर्गत ग्राम सभा जौरासी और ग्राम सभा स्यालनी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत अधिग्रहीत भूमि के स्वामियों के मुआवजे को लेकर एक विशेष शिविर लगाया जाएगा।

यह शिविर 8 अक्तूबर को आयोजित होगा, जिसमें राजस्व विभाग और पीएमजीएसवाई के अधिकारी भाग लेंगे। शुक्रवार को इस बारे में जौरासी के पूर्व ग्राम प्रधान चंडी प्रसाद कुकरेती ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए जिन भूमि स्वामियों की जमीन अधिग्रहीत की गई है, वे अपने मुआवजे को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के समाधान हेतु शिविर में भाग लें। उन्होंने सभी भू स्वामियों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

घंटाघर बनाने के बजाय विकास पर ध्यान दें सरकार

जयन्त प्रतिनिधि ।कोटद्वार : सरकार की ओर से कोटद्वार के इंटर कालेज चौराहे पर घंटाघर निर्माण के खिलाफ नगर निगम के निवर्तमान पार्षदों ने शुक्रवार से मोर्चा खोल दिया है। मौके पर निवर्तमान पार्षदों ने घंटाघर के स्थान पर बीरबाला तीलू रौतेली की प्रतिमा को चौराहे के बीच स्थापित करने की मांग की। इस संबंध में निवर्तमान पार्षदों की मालवीय उद्यान में शुक्रवार को आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से अब तक कोटद्वार के विकास में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया गया है।

मालन पुल अभी तक भी बनकर तैयार नहीं हो पाया है, शहर में निराश्रित गो वंशों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन मूलभूत समस्याओं पर ध्यान देने के स्थान पर सरकार घंटाघर निर्माण करने जा रही है, जो अनुचित है। कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान कोटद्वार में मेडिकल कालेज स्थापना, लालढ़ांग-चिलरखाल मोटर मार्ग निर्माण और कोटद्वार को जिला बनाने सहित कई वायदे किए गए थे, लेकिन प्रदेश सरकार के कार्यकाल के तीन साल बीतने के बाद भी धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। कहा कि स्थानीय विधायक को जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए। मौके पर निवर्तमान पार्षदों ने घंटाघर के स्थान पर बीरबाला तीलू रौतेली की प्रतिमा को चौराहे के बीच स्थापित करने की मांग की। बैठक में सूरज कांति, सोनिया नेगी, सुखपाल शाह, रोहिणी देवी, विपिन डोबरियाल, विमला रावत और बीना नेगी आदि निवर्तमान पार्षद मौजूद रहे।

कमलेश कंडारी के निधन पर जताया शोक

उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने नैनीडांडा ब्लाक अध्यक्ष कमलेश कंडारी।

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने नैनीडांडा ब्लाक अध्यक्ष कमलेश कंडारी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इस दौरान सदस्यों ने दो मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की।

शोक सभा में वक्ताओं ने कहा कि कमलेश कंडारी का हिमालय हॉस्पिटल जौलीग्रांट, देहरादून में उपचार चल रहा था। जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया कि कमलेश कंडारी 2013 से वर्तमान तक लगातार उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे। डीयू से अध्ययन के दौरान छात्र राजनीति में सक्रिय रहने के उपरांत 1996 में उन्होंने अभिभाजित उत्तर प्रदेश में लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधानसभा चुनाव भी लड़ा। उन्होंने अपने गांव नैनीडांडा ब्लाक के ग्राम चैड में सेब के बगीचे भी विकसित किए हुए हैं। वह सदैव युवाओं को स्वजरोगार के प्रति जागरूक किया करते थे। वर्ष 2007-08 में कंडारी भारतीय जनता पार्टी संगठन जनपद कोटद्वार के जिला महामंत्री भी रहे। शोक व्यक्त करने वालों में लैंसडौन विधायक दिलीप रावत, रघुबीर बिष्ट, सतीश घिल्डियाल, अर्जुन पटवाल, दीपक नेगी, मधूसूदन, देवेंद्र नेगी, अजीम हैदर नकवी, विवेक मधवाल, धनपाल सिंह, अजेश रावत, डबल सिंह आदि मौजूद रहे।

प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे कोटद्वार के खिलाड़ी

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : थंग-टा फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली की ओर से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तीन दिवसीय थंग-टा मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में उत्तराखंड से प्रतिभाग करने वाली टीम में कोटद्वार के दो खिलाड़ी भी शामिल होंगे। शुक्रवार को ऑल उत्तराखंड मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि 30वीं राष्ट्रीय जूनियर थंग-टा मार्शल आर्ट प्रतियोगिता पांच से सात अक्तूबर तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित मल्टी परपज बैडमिंटन हॉल, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन शक्ति नगर में आयोजित होगी। जिसमें हैप्पी होम स्कूल कोटद्वार से 80 किग्रा भार वर्ग में सुजल सिंह एवं 52 किग्रा भार वर्ग में समीक्षा प्रतिभाग करेंगी। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम में दिल्ली पब्लिक स्कूल ऋषिकेश से 56 किग्रा भार वर्ग में पल्लवी रौतेला, 52 किग्रा भार वर्ग में सविनय और 60 किग्रा भार वर्ग में आशुतोषम शामिल किए गए हैं।

रामलीला मंचन को संरक्षित करने के लिए आगे आएं युवा पीढ़ी

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : श्री रामलीला मंचन एवं सांस्कृतिक समिति की ओर से शुक्रवार से 124वां मंचन शुरू हो गया है। मुख्य अतिथि महिताब सिंह रावत ने कहा कि धार्मिक और पौराणिक महत्व के इस आयोजन को संरक्षित करने के लिए युवा पीढ़ी को आगे आने की जरूरत है। उन्होंने समिति के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि रामलीला का 124वां मंचन इस बात को दर्शाता है कि पौड़ी की रामलीला उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है।

रामलीला का शुभारम्भ मुख्य अतिथि और रामलीला समिति के 90 वर्षीय वयोवृद्ध संरक्षक महिताब सिंह रावत ने किया। समिति के अध्यक्ष उमाचरण बड़थ्वाल ने सभी से सहयोग की अपील की। रामलीला मैदान में लीला गणेश वंदना से रामलीला की शुरुआत हुई। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती संवाद जब नीच निशाचर पाप करे से आरंभ होकर रावण दरबार में शुक्राचार्य द्वारा राक्षसों को दुरोपदेश देकर ऋषि मुनियों को सताना, ऋषियों से कर लेना, अयोध्या में राजा दशरथ की सभा, सुमंत दशरथ वार्तालाप, पुत्रष्ठी यज्ञ और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जन्म तक की लीला मंचित की गई। दशरथ सुमंत संवाद में दशरथ का गायन मेरे पुत्र नाहीं, पुत्र नाहीं, पुत्र नाहीं जी बड़ा मार्मिक रहा। महादेव की भूमिका में पारस, पार्वती आरती बहुगुणा, रावण जगत किशोर बर्थवाल, दशरथ सुदर्शन बिष्ट, सुमंत प्रदीप कंडारी, शुक्राचार्य वीरेंद्र जदली, श्रृंगी ऋषि डा. मदन मोहन नौडियाल, दूत गौतम, कैकई मोनिका वेदवाल, कौशल्या सोनम डोभाल, सुमित्रा संजना, वशिष्ठ पारस, ऋषि अनिल, अंशुमन, सचिन और वंश रहे। पार्श्व गायन गौरी शंकर थपलियाल, पुष्पा थपलियाल, उमाचरण बड़थ्वाल, मनोज रावत अंजुल, इंद्र मोहन चमोली, सर्वेंद्र रावत, प्रीती, कविता ममगाई, सुनंदा चमोली, सोनिका गैरोला, प्रेम बल्लभ पंत, अंकित नेगी और गौतम ने किया।

छात्रों को औषधीय पादपों के संरक्षण के बारे में बताया

श्रीनगर गढ़वाल : वन्य जीव सप्ताह के तहत गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान गढ़वाल क्षेत्रीय केंद्र श्रीनगर के तत्वावधान में शुक्रवार को कारगिल शहीद कुलदीप सिंह राजकीय इंटर कॉलेज खंडाह में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता जीबी पंत श्रीनगर केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. के चंद्र शेखर ने हिमालय में पाई जाने वाली जैव विविधता एवं उनके महत्व के बारे में विद्यार्थियों को बताया। मुख्य वक्ता वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. अरुण कुमार जुगराण ने हिमालयी क्षेत्र में उपस्थित जंगली फलों तथा औषधीय पादपों का वर्णन करते हुए उनमें उपस्थित पोषक तत्व तथा औषधीय गुणों की जानकारी दी एवं पादपों के संरक्षण की उपयोगिता के बारे में बताया। कार्यक्रम का संचालन भगवती प्रसाद गौड व शोधार्थी आशीष कुमार गुसाईं ने सयुंक्त रूप से किया।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लो0नि0वि0 पौड़ी

E Mail ID :- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

पत्रांक 1413/20ए0सी0 दिनांक 3/10/2024

"शुद्धि पत्र"

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र सं0 1354/20ए0सी0 दिनांक 26.09.2024 द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी। ठेकेदार संघ जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा ठेकेदार महासंघ के आवाह्न पर समस्त प्रदेश में कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा लगाई गई निविदाओं का बहिष्कार किया गया है, जिस कारण खण्ड में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण निविदा आमंत्रित एवं खोलने के समय को निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है।

पूर्व निर्धारित तिथि			संशोधित तिथि		
निविदा विक्रय की तिथि	निविदा आमंत्रण तिथि	निविदा खुलने की तिथि	निविदा विक्रय तिथि	निविदा आमंत्रण तिथि	निविदा खुलने की तिथि
दि0 27.09.2024 से दि0 03.10.2024 प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक)	दि0 04.10.2024 अपराह्न 3 बजे तक	दि0 04.10.2024 अपराह्न 3:30 बजे	दि0 04.10.2024 से 09.10.2024 (प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक)	दि0 10.10.2024 अपराह्न 2:00 बजे तक	दि0 10.10.2024 अपराह्न 3:30 बजे

शेष शर्तें यथावत रहेगीं।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

(0479/55)

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियन्ता/III/मुरादाबाद द्वारा ई टेन्डर निम्न टेन्डर संख्या के अन्तर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की कीमत तथा धरोहर राशि का भुगतान निविदा दाता द्वारा केवल **IREPS** पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपाजिट रसीद आदि स्वीकार्य नहीं होंगे।। टेन्डर से संबंधित अन्य जानकारी वैबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखें।

टेन्डर संख्या दिनांक	179-DRM-MB-24-25 Dt.04.10.2024	189-DRM-MB-24-25 Dt.04.10.2024	193-DRM-MB-24-25 Dt.04.10.2024	191-DRM-MB-24-25 Dt. 04.10.2024	195-DRM-MB-24-25 Dt. 04.10.2024
कार्य का नाम	Interlocking of 14 Number of L.C. gates TVU>50000 over Moradabad division.	Replacement of channel sleepers with H-Beam sleeper and associated work on bridge No.1125 UP in MB-RAC section under Sr.DEN-III/MB.	Bridge Repair work at various bridges in the section of SSE/W/SPN & Jacketing, Providing inspection steps, ballast retainer wall and epoxy pressure grouting work at various bridges under SSE/W/RAC in the section of ADEN/SPN.	Improvement Of Water Supply Installation By Providing a New Borewell In Replacement Of Pump No.7, Redevelopment of Pump No.8 at Railway colony RAC and completion of remaining work of pump under construction at goods siding at RAC in the section of SSE/W/RAC.	Civil work in c/w provision of RGM/Track machine siding at BEG, RAC, TLH, MIL, PMR, RYS, BE, CBJ, RMU and BTO in the section of ADEN/SPN and ADEN/BE under Sr.DEN-III/MB.
टेन्डर क्लोसिंग दिनांक/समय	28.10.2024 16:00	28.10.2024 16:00	28.10.2024 16:00	28.10.2024 16:00	28.10.2024 16:00
अनुमानित लागत	82,64,108.98	1,85,37,871.53	1,37,50,225.77	65,99,737.68	2,36,99,724.00
धरोहर राशि	1,65,300.00	2,42,700.00	2,18,800.00	1,32,000.00	2,68,500.00
बिडिंग स्टार्ट तिथि	14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024
आफर की वैधता	60 दिन	60 दिन	60 दिन	60 दिन	60 दिन
कार्य पूर्ण करने की अवधि	08 माह	08 माह	08 माह	08 माह	12 माह

नं. 75-W/2/3/WA/Publication दिनांक : 04.10.2024 3066/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

एक नजर

नवरात्र पर देवी मंदिरों में दर्शनों को पहुंचे भक्त

रुद्रप्रयाग : शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन भी जनपद के सिद्धपीठों में सुबह से भक्तों की भीड़ लगी रही। देवी मंदिरों में भक्तों ने मां की पूजा-अर्चना कर खुशहाली की प्रार्थना की। प्रसिद्ध सिद्धपीठ कालीमठ, कालीशिला, मठियाणाखाल, हरियाली देवी, चामुंडा माई, राकेश्वरी, चंडिका, गौरामाई, नारी देवी, नानतोली सहित कई देवी मंदिरों में नवरात्र के दूसरे दिन भी भक्तों द्वारा माता के जयकारे लगाए गए। दर्शनों को भीड़ लगी रही। भक्तों ने मंत्रोचार के साथ मां दुर्गा के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा-अर्चना की गई। पुजारियों द्वारा मां का पंच स्नान के साथ आरती की गई। मां के भक्त दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंच रहे है। कालीमठ मंदिर में दूर दराज क्षेत्रों से बडी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। कालीमठ के पुजारी जेपी गौड ने बताया कि नवरात्र में सच्चे मन से मां काली के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बताया कि कालीमठ में प्रदेश के कई जनपदों से भक्तजन मां काली के दर्शनों के पहुंच रहे है। (एजेंसी)

जिले की समस्याओं को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन

रुद्रप्रयाग : जनपद की विभिन्न समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी जिला संयोजक ने जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की। इस दौरान उन्होंने अनेक समस्या से जुड़ा ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। आम आदमी पार्टी के संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने जिलाधिकारी सौरभ गहरवार को दिए ज्ञापन में कहा कि जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में लावारिश पशु सड़कों पर घूम रहे है। जिससे यह पशु व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जबकि शहर में जाम का कारण भी बन रहे है। ऐसे पशुओं के लिए कांजी हाउस की व्यवस्था की जाए। शहर में आवारा कुत्तों को रैबीज के इंजेक्शन लगवाकर आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाए। शहर के सीसीटीवी कैमरों की सही मॉनिटरिंग करने, शहर में बनी नालियों की नियमित साफ सफाई करवाने, तूना-बौंठा मोटरमार्ग की स्थिति में सुधार लाने, वृद्धावस्था पेंशन से वंचित लोगों की पेंशन लगाने, वर्ष 2011 में आठ हाईस्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण होने के बाद पदों का सृजन न होने की जानकारी दी। कहा कि उक्त समस्याओं पर शीघ्र कार्यवाही की जाए। (एजेंसी)

तुंगनाथ ट्रैक पर सीओ ने जाने यात्री एवं पर्यटकों के अनुभव

रुद्रप्रयाग : पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने ऊखीमठ थाने के साथ ही चोपता में रिपोटिंग चौकी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अनेक व्यवस्थाएं जांची साथ ही निर्देश दिए कि पुलिस से संबंधी कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। जबकि जनता की हर संभव मदद करने के लिए भी निर्देशत किया गया। ऊखीमठ थाने में निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे पैदल यात्रा कर तृतीय केदार तुंगनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान तुंगनाथ के दर्शन किए। जबकि इस दौरान चोपता में रिपोटिंग चौकी का निरीक्षण किया। चोपता चौकी के निरीक्षण के दौरान उन्होंने रमणीक स्थल चोपता, दुगलविट्टा और आसपास के क्षेत्र की व्यापक जानकारी ली। साथ ही तुंगनाथ मन्दिर पैदल ट्रैक पर आने वाले ट्रैकर, पर्यटकों और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस के अधिकारी और जवानों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि शीतकाल में भी यहां बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है इसलिए इस क्षेत्र में पुलिस जवानों को हर समय अलर्ट रहने की जरूरत है।

हर दुकान पर चस्पा करें रेट लिस्ट : डीएम

नई टिहरी : डीएम के निर्देश पर टिहरी के तहसीलदार मो. शादाब नेतृत्व में नगर पालिका, खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट और सब्जी की दुकानों का निरीक्षण किया। पॉलीथिन का प्रयोग करने पर दो दुकानदारों के चालान किए गए। उन्होंने सभी दुकानदारों और खासकर फल और सब्जी विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से बड़े साइज में रेट लिस्ट चस्पा करने के निर्देश दिए। कहा कि उपभोक्ताओं सहित सामाजिक संगठनों ने टिहरी में सब्जी और फलों के दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की शिकायत की है। इस संबंध में एसडीएम संदीप कुमार का कहना है कि किराना, सब्जी, फल, डेयरी प्रोडक्ट के दामों पर निगरानी के लिए टीम नियमित रूप से बाजारों का निरीक्षण कर रही है। उन्होंने सभी दुकानदारों से एफएसएसएआई का लाइसेंस, साफ-सफाई और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर पालिका के ईओ मोहम्मद कामिल, सफाई निरीक्षक आशीष तोपवाल, विकास राजन, शीशपाल सिंह सजवाण, कुशालानंद उनियाल आदि मौजूद थे। (एजेंसी)

दैनिक अखबारों को प्रतिदिन समाचार निरीक्षा पंजिका में दर्ज करें : अपर निदेशक

जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड के अपर निदेश-क/जनपद नोडल अधिकारी आशीष कुमार त्रिपाठी द्वारा शुक्रवार को जिला सूचना कार्यालय पौड़ी गढ़वाल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय पटल सहायकों से कार्यों की जानकारी लेते हुए पत्रावलियों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में अपर निदेशक ने जिला सूचना कार्यालय पौड़ी का निरीक्षण करते हुए डिस्पैच पंजिका, डाक पंजिका, समाचार पत्र निरीक्षा पंजिका सहित अन्य का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि दैनिक अखबारों को प्रतिदिन समाचार निरीक्षा पंजिका में दर्ज करें। कार्यालय में सभी पंजिका सुव्यवस्थित पाये जाने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। वहीं उन्होंने सूचना कार्यालय भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए नये भवन तलाशते हुए वहां कार्यालय शिफ्ट करने के निर्देश दिये। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पत्रकार कल्याण की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा पत्रकार कल्याण कोष को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। कहा कि किसी पत्रकार के आकस्मिक निधन की स्थिति में उनके आश्रितों को दी जाने वाली सहायता की प्रक्रिया को और सुगम और तेज बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि नई पत्रकार मान्यता नियमावली पर कार्य चल रहा है जिसमें तहसील स्तर तक मान्यता देने का निर्देश भी मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। सूचना विभाग और जनपद स्तरीय पत्रकारों के मध्य संवाद बढ़ाने और पत्रकारों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से सूचना विभाग के जनपद नोडल अधिकारियों द्वारा क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है। इस मौके पर प्रभारी सूचना अधिकारी सुनील सिंह तोमर, संरक्षक प्रमोद बर्तवाल, कनिष्ट सहायक पुष्कर सिंह बिंजोला, वरिष्ठ पत्रकार अनिल बहुगुणा, त्रिभुवन उनियाल, अजय रावत, अनिल भट्ट, जगमोहन डांगी, मनोहर बिष्ट, कुलदीप बिष्ट, मुकेश आर्य, मुकेश सिंह, सिद्वांत उनियाल, मुकेश बछेती, प्रदीप नेगी, दीपक बड़थ्वाल, महेंद्र सिंह, मनीष खुगशाल, डबल सिंह, विजय बहुगुणा, भगवान सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के अपर निदेशक आशीष कुमार त्रिपाठी जिला सूचना कार्यालय में कर्मचारियों से जानकारी लेते हुए।

धामी सरकार ने तीन साल में बनाई 1481 किमी. लंबी ग्रामीण सड़क

इस अवधि में 519 नई सड़कों और 195 सेतुओं का निर्माण किया गया

जयन्त प्रतिनिधि। देहरादून : पुष्कर सिंह धामी सरकार के तीन साल बेमिसाल के दौरान पीएमजीएसवाई में उत्तराखण्ड में कुल 1481 किमी लंबाई युक्त 519 सड़कों का निर्माण किया गया, जिस कारण 250 सौ से अधिक आबादी वाले 35 नए गांवों तक सड़क पहुंच पाई।

धामी सरकार के तीन साल के कार्यकाल में जहां योजना के तहत कुल 1481 किमी. लम्बाई युक्त 519 नई सड़कों और 195 सेतुओं का निर्माण किया गया, वहीं पहले से निर्मित 159 किमी. लंबी 61 ग्रामीण सड़कों का भी अपग्रेडेशन किया गया। इन सड़कों और पुलों के निर्माण पर कुल 2310 करोड़ रुपए व्यय किए गए। धामी सरकार के दौरान 250 से अधिक जनसंख्या की 35 बसावटों को सड़क से जोड़कर ग्रामीणों की आवाजाही सुगम की गई है। योजना के तहत प्रथम और दूसरे चरण के कार्य अब पूरे होने की स्थिति में पहुंच गए हैं, अब पीएमजीएसवाई तृतीय चरण के तहत पूर्व में निर्मित सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए 1824 करोड़ रुपए की स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है, इसके तहत कुल 2288 किमी. लंबी सड़कों का अपग्रेडेशन किया जाना है। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सड़क से वंचित आठ बसावटों को सड़क सम्पर्क से जोड़े जाने के लिए 119 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गई है। इसके बाद प्रदेश में 150 से कम जनसंख्या की कुल 1796 बसावटें ही ऐसी रह गई हैं, जहां सड़क नहीं पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसम्बर, 2000 में केंद्र की तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेई सरकार ने प्रारम्भ की थी।

शिक्षा मानव को महामानव बनाने की प्रक्रिया : प्रो. श्रीवास्तव

नई टिहरी : गढ़वाल केंद्रीय विवि के एसआरटी परिसर बादशाहीथौल के शिक्षा विभाग में एनईपी 2020 में चुनौती और समाधान विषय पर प्रो. आरके श्रीवास्तव द्वारा एक व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर प्रो. श्रीवास्तव का शाल ओढ़ाकर सम्मान भी किया गया। शुक्रवार को पूर्व विभाग एवं संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग एसआरटी परिसर प्रो श्रीवास्तव ने एक विशिष्ट व्याख्यान प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने बताया कि शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। शिक्षा से व्यक्ति मानव से महामानव बनता है। जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा समर्थ होती है। शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष सुनीता गोदियाल ने कहा कि हमारे विभाग के प्रशिणार्थी प्रत्येक वर्ष दो पत्रिकाओं का सम्पादन करते हैं। जिससे उसकी प्रतिभा का विकास होता है। वे अपनी व्यावसायिक दक्षता को प्राप्त करते हैं। हमारे विभाग ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक योजना बनाई है। इन्टर्नशिप में जाने वाले सभी प्रशिणार्थियों के लिए पौधरोपण असाइनमेंट दिया है। प्रत्येक प्रशिणार्थी को विद्यालय में जाकर पौधरोपण करना है। प्रत्येक दिन उसकी सिंचाई के साथ निराई-गुड़ाई करनी है। पहले दिन तथा अन्तिम दिवस की फोटो खींचकर एक रिपोर्ट बनाकर विभाग में जमा भी करवानी है। इसे आन्तरिक मूल्यांकन का भाग बनाया गया है। मंच संचालन डा. मनोज नौटियाल ने किया। इस अवसर पर डा. नीरज जोशी, डा. सुमनलता, डा. देवम, डा. हेमराज, डा.अखिलेश कुमार गौतम, डा.अरविन्द कुमार, संगीता, कृष्णा, गौरव तड़ियाल आदि मौजूद रहे। (एजेंसी)

मंत्री बहुगुणा बोले खेल युवाओं में टीम भावना को बढ़ाता है

नई टिहरी : कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में शुक्रवार को खेल प्रतियोगिताओं का बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरव बहुगुणा ने शुभारंभ किया। मौके पर स्वागत में छात्रों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। शुक्रवार को खेल प्रतियागिताओं के शुभारंभ से पूर्व अतिथि के सम्मुख विद्यालयों ने मार्च पार्स्ट निकाला। अतिथियों के स्वागत में गुरु रामराय पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने स्वागतगान के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री बहुगुणा ने कहा कि खेल खिलाड़ियों के अंदर जीत भावना एवं टीम भावना को उजागर करती है। खेल ही देश की नई पीढ़ी को नशे से दूर रख सकता है। मेला संयोजक मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्य अतिथि सौरव बहुगुणा का समस्त क्षेत्र एवं खेल से जुड़े लोगों की तरफ से आभार व्यक्त किया।

न्याय पंचायत, विकासखंड, जिला स्तर पर आयोजित होंगी खेल प्रतियोगिताएं

जयन्त प्रतिनिधि।

रूद्रप्रयाग : मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में खेल महाकुंभ-2024 के सफल संचालन हेतु बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ खेल महाकुंभ का सफल संचालन करने के निर्देश दिए।आयोजित बैठक में जिला युवा कल्याण व प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी वरद जोशी ने बताया कि 04 अक्टूबर से 07 नवंबर, 2024 तक न्याय पंचायत स्तर पर अंडर-14 व अंडर-17 बालक व बालिका वर्ग में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो एवं वालीबाल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता को क्रमशः तीन सौ, दौ सौ व डेढ़ सौ रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह 25 अक्टूबर से 15 नवंबर, 2015 तक विकासखंड स्तर पर इसी विधा व आयु वर्ग में आयोजित प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिसमें प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को पांच सौ, द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता को 400 तथा तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता को 300 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद जनपद स्तर पर 16 नवंबर से 10 दिसंबर, 2024 तक अंडर-14, 17 एवं अंडर-20 बालक व बालिका वर्ग में फुटबाल, बैडमिंटन, जूड़ो, बॉक्सिंग, टेबिल टेनिस, ताईक्वांडो, कराटे, बास्केटबॉल हैंडबाल, मलखम्ब, हॉकी मुर्गा झपट में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पहले स्थान पर 800 रुपए दूसरे स्थान पर 600 तथा तीसरे स्थान प्राप्तकर्ता को 400 रुपए की नकद धनराशि पुरस्कार आवंटित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को न्याय पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों का दो दिन के अंदर पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पंजीकरण हेतु क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, क्रीड़ा अधिकारी सहित संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को आपसी समन्वय के साथ सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रमेंद्र कुमार बिष्ट, पुलिस निरीक्षक सुरेश चंद्र बलूनी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आशुतोष, प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी मनोज सिंह चैहान, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी राधिका, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र राहुल डबराल, खंड शिक्षा अधिकारी अतुल सेमवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए।

कैंसर के मरीजों के लिए बेस अस्पताल में खुली पैलिएण्टिव केयर ओपीडी एवं वार्ड

माह के पहले और तीसरे सोमवार को लगेगी ओपीडी

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत एवं विधायक रूद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी ने शुक्रवार को कैंसर के मरीजों के लिए ऑन्कोलॉजी एंड पैलिएटिव केयर ओपीडी की सुविधा का शुभारंभ किया।

इसके साथ ही गढ़वाल भर से आने वाले लोगों तथा चार धाम यात्रियों की सहायता हेतु हेल्प डेस्क का भी बेस अस्पताल में शुभारंभ किया। एनेस्थीसिया विभाग के असि. प्रोफेसर डॉ. मोहित को पैलिएटिव केयर ओपीडी का नोडल बनाया गया है। इस अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि कैंसर व असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों की देखरेख एवं स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो तो वह पैलिएटिव केयर ओपीडी में आकर अपनी समस्या का हल कर सकते है। यहां एनेस्थीसिया व सपोर्टिंग चिकित्सको के डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। जबकि कैंसर स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजी सर्जन डॉ. अजीत तिवारी हर माह के पहले सोमवार और तीसरे सोमवार को ओपीडी लगायेंगे। बेस अस्पताल में पहली ओपीडी सात अक्तूबर से लगेगी। डॉ. रावत ने कहा कि बेस अस्पताल में हर रोग के इलाज के डॉक्टरों की तैनाती से लेकर दवा और संसाधनों की सुविधा में लगातार इजाफा किया जा रहा है। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीएमएस रावत ने ऑन्कोलॉजी एंड पैलिएटिव केयर ओपीडी की शुरुआत करने पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री का आभार प्रकट किया। कहा कि कैंसर के साथ-साथ असाध्य रोगों से संबंधी मरीजों को बेस अस्पताल में पैलिएटिव केयर की सुविधा मिलने से लाभ मिलेगा। जबकि स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजी सर्जन की ओपीडी लगने से लोगों की कैंसर संबंधी इलाज व जांच पड़ताल संभंव हो पायेगी। शुरुआत में ही पता चलने पर मरीज पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। डॉ. रावत ने कहा कि हेल्प डेस्क में ओपीडी, डॉक्टर, वार्ड, ब्लड़ बैंक, लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, औषधी कक्ष सहित तमाम जानकारियां लोगों को मिल पायेगी। यहीं नहीं हेल्प डेस्क में अस्पताल में हेल्प लाइन नंबर 18001802778 से भी जानकारी ली जा सकेगी। कार्यक्रम में बेस चिकित्सालय के एमएस डॉ. अजेय विक्रम सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सुषमा रावत, मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ. केएस बुटोला, नेत्र रोग विभाग के एचओडी डॉ. युसूफ रिजवी, कैंसर विभाग की एचओडी इंदिरा यादव, पैथोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉ. दीपा हटवाल, ब्लड़ बैंक प्रभारी डॉ. सतीश कुमार, एमएसडब्ल्यू जतिन सिंह, विजय जमलोकी, भवतोश सेमवाल सहित अन्य लोग मौजूद थे।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ऑन्कोलॉजी एंड पैलिएटिव केयर ओपीडी का शुभारंभ करते हुए।

पैलिएटिव केयर ओपीडी क्या होती है

कैंसर व असाध्य रोग में रोगियों में तरह-तरह के शारीरिक लक्षण शरीर के किसी भी अंग में बहुत समय से गांठ रहना, शरीर के कसी भी हिस्से में सतत दर्द बने रहना, खून का लगातार रिसाव, पेशाब करने में काफी दिनो की तकलीफ, पेट में बहुत दिनों का दर्द, बार-बार बेसुधी, लम्बे समय से थकान रहना, भोजन निगलने में परेशानी, नींद व भूख की लगातार कमी, लगातार सांस फूलना की दिक्कत आदि होना है। जिससे उनकी मानसिक परेशानियां भी बढ़ने लगती है। ऐसे में कैंसर व असाध्य रोग के मरीजों को पैलिएटिव केयर एक सबसे अच्छा केन्द्र होता है। जहां मरीजों की काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक मजबूती, आध्यात्मिक शक्ति व दर्द को कम कर सकारात्मक रखने में मदद मिलती है। जिससे कि असाध्य रोगी की इम्यूनिटी बढ़ने के साथ जीवन प्रत्याशा भी बढ़ जाती है।

उत्तराखंड में मिला लापता हुआ दिल्ली का युवक

चमोली : दिल्ली का एक शख्स घूमने के लिए उत्तराखंड गया था। यहां घूमने के दौरान वो लापता हो गया। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दिल्ली के 40 तीर्थयात्रियों का एक समूह चमोली जिले के रुद्रनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए गया था। यात्रा के बाद बाकी के तीर्थयात्री लौट आए लेकिन आकाश गुप्ता नाम का यात्री लापता हो गया।

डीएम ने बताया कि मंदिर पहुंचने के लिए कठिन रास्तों का सफर तय करना होता है। आकाश को ढूंढने के लिए टीम लगाई गई है। इस घटना की जानकारी देते हुए चमोली जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने बताया कि दर्शन करने गए सभी यात्री सुरक्षित वापस आ गए लेकिन दिल्ली का रहना वाला आकाश गुप्ता गुरुवार देर शाम को पुंग पड़ाव के पास से लापता हो गया। संदीप ने बताया कि आकाश को ढूंढने के लिए वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि रुद्रनाथ मंदिर की तीर्थयात्रा कठिन रास्तों से होकर जाती है। ऐसे में यहां पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों को सागर गांव और अनुसूया गेट से होते हुए मंदिर तक करीब 20 किलोमीटर की यात्रा करने पड़ती है। इस रास्तों में 20 किलोमीटर तक घने जंगलों और घास के मैदानों और खड़ी ढलानों को पार करना पड़ता है। डीएम ने बताया कि दिल्ली से आए तीर्थियात्रियों के इस जत्थे ने सागर गांव से अपनी यात्रा शुरू की थी। बता दें कि रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के पंचकेदार मंदिर समूह का हिस्सा है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए दुर्गम रास्तों का सफर तय करना पड़ता है। इन मंदिरों के समूह में केदारनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, कल्पेशवर और मध्यमहेश्वर मंदिर मौजूद हैं। डीएम ने बताया कि मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में तीर्थायात्री यहां पहुंचते हैं और भगवान शिव की पूजा करने करते हैं। इस दौरान यात्रियों के समूह से बिछड़ जाने की घटनाएं आम हैं। आकाश को जल्दी ही ढूंढ लिया जाएगा। चमोली के अपर जिला सूचना अधिकारी रवींद्र सिंह नेगी ने यहां बताया कि आकाश गुप्ता (33) को पुलिस, वन विभाग, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिवादन बल और जिला आपदा प्रबंधन की संयुक्त टीम द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान दोपहर करीब 12 बजे सुरक्षित ढूंढ लिया गया। (एजेंसी)

ठेकेदारों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लोनिवि दफ्तर में किया प्रदर्शन

चमोली : शुक्रवार को देवभूमि कल्याण समिति के ठेकेदारों ने 10 करोड़ तक के कार्य उत्तराखंड के मूल निवासियों को दिए जाने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लोक निर्माण विभाग दफ्तर गौचर में प्रदर्शन किया। गुस्साएं ठेकेदारों ने नारेबाजी कर सरकार का पुतला दहन कर कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में सीएम को ज्ञापन भी भेजा। ठेकेदारों ने कहा कि वे अपने संसाधनों से काम करते हैं। उसके बावजूद भी उनका भुगतान समय से नहीं किया जाता है। कहा कि निविदाएं छोटी लगनी चाहिए। फेज प्रथम व द्वितीय के कार्य छोटे हिस्सों में होकर एक साथ लगने चाहिए, जिससे डी और सी श्रेणी के ठेकेदार ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। पांच करोड तक के कार्य सिंगल बिड में एवं 10 करोड तक के कार्य उत्तराखंड मूल के निवासियों को मिले।

ईवीएम वेयर हाउस का किया निरीक्षण

चमोली : जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने शुक्रवार को राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ईवीएम व वीवीपैट मशीनें डबल लॉक में सुरक्षित पाई गई। जिला मजिस्ट्रेट ने वेयर हाउस में विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। वेयर हाउस में ईवीएम निरीक्षण करने के दौरान पूरी प्रक्रिया की फोटो एवं वीडियोग्राफी की गई। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, नायब तहसीलदार दीप्ती शिखा, बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष गोविन्द सिंह बजवाल, कांग्रेस पार्टी के नगर महामंत्री मदन लोहानी, आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रभारी अनूप सिंह रावत आदि मौजूद थे। (एजेंसी)

ग्राहक के सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए

चमोली : उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग और नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, नासवी द्वारा शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में सुरक्षित आहार परोसने (सर्व सेफ फूड) विषय पर स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के साथ प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। जिसमें स्वच्छता पूर्वक स्ट्रीट फूड परोसने के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान स्ट्रीट खाद्य विक्रेताओं एवं खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता की जानकारी दी गई। विक्रेताओं को निजी स्वच्छता, साफ कपड़े, साफ एप्रन और बालों को ढक कर भोजन बनाने, कार्यस्थल की साफ सफाई, गुणवत्तापरक सामग्री का इस्तेमाल, भोजन में रंग या अन्य मिलावट न करने, अखबार में भोजन न परोसने के साथ पकवान बनाने तथा कचरा निस्तारण के लिए ढके हुए डस्टबिन का इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में सभी विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा किट जिसमें एप्रन, कैप, ग्लव्स, तौलिया, डस्टर दिए गए। ट्रेनिंग के बाद एफएसएसएआई द्वारा फोस्टक सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में 150 फूड विक्रेताओं ने प्रतिभाग किया। दिल्ली से आई ट्रेनर सिया मिश्र ने बताया कि खाद्य सुरक्षा का पालन न करने पर विक्रेताओं पर सजा और मुआवजा का भी प्रावधान है।

अनुसूचित जाति के लोगों की हर समस्या का करें समाधान

रुद्रप्रयाग : उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कमसाल, कांदी, टेमरिया समेत गांवों में बैठक कर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए।

इस दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति व्यक्तियों के लिए संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। मुकेश कुमार ने अनुसूचित जाति के लिए जो भी योजनाएं संचालित हो रही है, उनका विभिन्न गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को पूरा लाभ दिया जाए। कहा कि अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को प्रथम पायदान पर लाने तथा उसे विकास योजनाओं की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

इस अवसर पर अनुसूचित जाति के जन प्रतिनिधियों एवं व्यक्तियों ने मुख्यतः पेंशन, पेयजल, आवास, सोलर लाइट, गौशाला, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा, सड़क मार्ग एवं बारात घर बनाए जाने संबंधी समस्याएं दर्ज कराई गई। बैठक में पूर्व विधायक आशा नौटियाल, अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य विशाल मुखिया, जिला पंचायत राज अधिकारी प्रेम सिंह रावत, खंड विकास अधिकारी प्रवीण भट्ट, समाज कल्याण अधिकारी हर्षवर्धन भट्ट सहित अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि एवं अनुसूचित जाति के लोग मौजूद थे। (एजेंसी)

जयन्त
संस्थापक
स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और स्वामी
नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित
—सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469 / 79
फोन / फैक्स 01382—222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail: nagendra.uniyal@gmail.com